



Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Published By



Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001 Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org, Phone:011-23005850

विषय सूची

1.	परिवर्तन की ओर पश्चिम बंगाल	4
2.	पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए बदलाव के निहितार्थ	7
3.	भाजपा की रणनीति	9
4.	पश्चिम बंगाल की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन	11
5.	पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कथन	12
6.	ममता सरकार का भ्रष्टाचार	13
7.	जनविरोधी ममता सरकार	20
8.	तृणमूल की तानाशाही	27
9.	पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा	30
10.	तृणमूल कांग्रेस की मर्यादाहीन राजनीति	39
11.	तुष्टिकरण की राजनीति	41
12.	संघीय ढांचे को तहस-नहस करने में जुटी हुई हैं ममता बनर्जी	47
13	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संकट	52
14.	पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं की स्थिति	53
15	परिवर्तन की राह पर पश्चिम बंगाल	57
16.	चयनित संदर्भ सूची	59

परिवर्तन की ओर पश्चिम बंगाल

स्वडंबना ही है कि जो बंगाल कभी देश को दिशा देता था,

जहाँ की आध्यात्मिक चेतना सम्पूर्ण समाज को ऊर्जा प्रदान करती थी; आज वह बंगाल हिंसा, कुशासन और तृष्टिकरण की राजनीति के चंगुल में पिस रहा है. ममता बनर्जी के राज में आज बंगाल के वातावरण में अशांति के सिवा कुछ नहीं है. राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, जहां बंगाल में शांति हो

सर्वविदित है कि इसी बंग भूमि पर गुरुदेव रिबन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कर पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया था. इस भूमि पर जन्मे राम कृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, बंकिमचन्द्र चटर्जी, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विद्वानों ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों के माध्यम देश को एक नयी दिशा देने का काम किया, लेकिन पिछले पांच दशक का इतिहास देखें तो बंगाल हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया. ऐसे में प्रश्न उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है?

दरअसल ब्रिटिश हुकुमत ने तो बंगाल की जो दुर्दशा की सो की ही, लेकिन आजादी के पश्चात् भी ये राज्य जिन लोगों के शासन में रहा, उनकी नीतियों ने इसका विनाश करने का ही काम किया. आजादी के बाद राज्य में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब तृणमूल कांग्रेस, इन तीन दलों का शासन रहा है. इन तीनों ने अपने-अपने शासन में राज्य को दुर्दशा तक पहुंचा दिया. 1950 में देश के औद्योगिक विकास में अकेले जिस बंगाल की 27% भागीदारी रहती थी, वो आज सिकुड़ते-सिकुड़ते महज 3.39 प्रतिशत होकर रह गयी है. 1955 में दवाओं का 70 फीसदी उत्पादन बंगाल में होता था जो कि आज गिरकर 8 प्रतिशत पर पहुँच चुका है.

कांग्रेस के शासन की बदहाली से ऊबकर लोगों ने 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता सौंपी थी, लेकिन करीब साढ़े तीन दशक के शासन में कम्युनिस्टों ने भी राज्य की दुर्गति ही की. कम्युनिस्ट शासन में राज्य के उद्योग-धंधे चौपट हो गए, हिंसा और अराजकता का बोलबाला बढ़ा, जिससे त्रस्त आकर राज्य की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया, लेकिन धीरे-धीरे अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिन कम्युनिस्टों का विरोध करके ममता सत्ता में आई थीं, वे खुद उन्हीं की तरह बन चुकी हैं.

2011 से 2018 के बीच देश में बिजली की खपत 1 फीसदी बढ़ी है. दुनियाभर में बिजली की खपत विकास का एक बड़ा पैमाना माना जाता है. लेकिन बंगाल में शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ कोई कारखाने ही नहीं हैं, इसलिए राज्य इस मामले में भी पिछड़ा हुआ है.

आज के इस इंटरनेट युग में जब सभी राज्य अपने-अपने ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच बढ़ाने में लगे हैं, तो बंगाल इस मामले में भी बेहद सुस्त गित से बढ़ रहा है. आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात के 5590 गांव, बिहार के 5904 गांव और ओडिशा के 3645 गांव इंटरनेट से जुड़े हैं, लेकिन बंगाल इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद जुलाई 2019 तक सिर्फ 2170 गांवों को ही

इंटरनेट से जोड़ सका है.

इसके अलावा बंगाल की ममता सरकार केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि जैसी जनकल्याण की योजनाएं भी इस डर से लागू नहीं कर रही हैं कि अगर इसका लाभ किसानों और गरीबों को मिला तो वह भाजपा को वोट दे देंगे. ममता की इस ओछी राजनीति के कारण बंगाल के 67 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि से वंचित होना पड़ रहा है. इतना ही नहीं, केंद्र की योजना को लागू करने की स्थिति में उसका नाम ही बदल दिया जा रहा. नीति आयोग की बैठकों में ममता बनर्जी हिस्सा नहीं लेती. वे बहुमत से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री मानने से भी इनकार कर चुकी हैं.

कुल मिलाकर ममता के शासन से बंगाल की जनता बुरी तरह से त्रस्त है. मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य सरकार उससे कटमनी यानी लाभार्थी को योजना का लाभ देने के लिए पैसे वसूल रही है. राज्य की शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है. कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल इस वक्त घोर अंधेरे में है, जिसे भाजपा में विकास की रौशनी दिखाई दे रही है. लोकसभा चुनाव तथा कम्युनिस्ट शासन में राज्य के उद्योग-धंधे चौपट हो गए, हिंसा और अराजकता का बोलबाला रहा, जिससे त्रस्त आकर राज्य की जनता ने ममता बनर्जी के नेतृत्व पर विश्वास दिखाया, लेकिन धीरे-धीरे अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जिन कम्युनिस्टों का विरोध करके ममता सत्ता में आई थीं, वे खुद उन्हीं की तरह बन चुकी हैं.

उससे पूर्व हुए पंचायत चुनावों के परिणाम इसी तरफ़ इशारा करते हैं. लोकसभा चुनाव में बंगाल में भाजपा की विजय, निश्चित ही असाधारण विजय है.

बंगाल में भाजपा के प्रति बढ़ता जनसमर्थन यह दिखाता है कि पार्टी ने संगठित और सुनियोजित रणनीति के साथ राज्य में चुनाव लड़ा. बंगाल का प्रत्येक कार्यकर्ता इस चुनाव में तमाम विघ्न-बाधाओं के बावजूद पूरी शक्ति और साहस के साथ डटा रहा. इस प्रकार पार्टी ने राज्य की सरकार के प्रति आक्रोशित जनता का विश्वास अपने पक्ष में मोड़ने में सफलता पाई. समूचे देश ने देखा कि कैसे भाजपा के बढ़ते प्रभाव से बौखलाई ममता बनर्जी न केवल राजनीतिक हिंसा पर उतर पड़ी थीं, बल्कि मतदाताओं को भी डराने का प्रयास किया गया. बावजूद इसके भाजपा की सफलता ममता के अलोकतांत्रिक आचरण पर लोकतंत्र का तमाचा ही कहा जाएगा.

बंगाल का एक अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है. यह राज्य आध्यात्म, साहित्य, शांति और ज्ञान का केंद्र बिंद् रहा है, लेकिन आज स्थिति इसके उलट हो गई है. बंगाल पतन की कगार पर है. जिस सोनार बांग्ला की कल्पना हमारे मनीषियों ने की थी, वह नेपथ्य में जा चुकी है. ऐसे में, आवश्यक हो चला है कि बंगाल को कुशासन के चंगुल से निकालकर पुनरुत्थान के पथ पर अग्रसित किया जाए. राज्य की जनता के मन में भाजपा के हाथों ही राज्य के उद्धार की आशा जग चुकी है, जिसका संकेत उसने लोकसभा चुनावों में दिया है और निस्संदेह विधानसभा चुनावों में वो भाजपा को बहुमत देकर राज्य के विकास को सुनिश्चित करेगी. इस बुकलेट में तृणमूल की राजनीतिक हिंसा, तानशाही शासन व्यवस्था, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण इन सबके विवरण के साथ-साथ बंगाल के वर्तमान परिदृश्य की जानकारी आपको प्राप्त होगी.

पश्चिम बंगाल की राजनीति में हुए बदलाव के निहितार्थ



कूचिबहार में रैली को संबोधित करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

श्चिम बंगाल में भाजपा की जीत एक

साथ कई संदेश को समेटे हुए है, जिसको समझने की आवश्यकता है. सर्वविदित है कि इस लोकसभा चुनाव में बंगाल ही एक ऐसा राज्य था, जहाँ चुनाव के प्रत्येक चरण में हिंसा हुई. तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में अराजकता का माहौल बना रखा है. बंगाल में भाजपा के लिए चुनौती कठिन थी. कदम-कदम पर ममता सरकार अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरूपयोग करके बीजेपी के लिए बाधाएं खड़ी कर रही थीं. राज्य सरकार बीजेपी के नेताओं की पिछले कुछ समय से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तृष्टिकरण का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, इससे समाज का एक वर्ग खुद को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहा था. उपेक्षा और वोटबैंक की राजनीति से त्रस्त बंगाल की जनता ने तृष्टिकरण की राजनीति को खारिज़ किया है.

रैलियों, सभाओं के लिए अनुमति नहीं दे रही थी, हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं होती थी तथा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी हत्या के ढेर सारे मामले सामने आ रहे थे. पूरी तरह अराजकता के वातावरण में भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी. हिंसा से भयभीत हुए बगैर भाजपा कार्यकर्ता ऊर्जा के साथ काम किए. देखा जाए तो हिंसा के सहारे अपनी राजनीति को आगे बढाने वाले वामपंथियों को जैसे बंगाल की जनता ने पूरी तरह से खारिज़ कर दिया है, उसी तरह ममता को भी जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि बंगाल की राजनीति में हिंसा के लिए कोई जगह नही है, यकीनन भाजपा की यह विजय हिंसा और तानाशाही की राजनीति पर मतदाताओं द्वारा दी गई करारी चोट है. गौरतलब है कि सिंडिकेट, बाहुबल और धनबल के सहारे चली आ रही भष्ट राजनीति के दिन अब लद चुके हैं. मूल्य आधारित राजनीति अब जनता को रास आने लगी है. इस चुनाव परिणाम का एक निहितार्थ यह भी निकलकर आ रहा है कि बंगाल की जनता राजनीति में स्पष्ट नीतियों और कुशल नेतृत्वकर्ता में ही अपने देश व राज्य का सुनहरा भविष्य देख रही है, ना कि भाई-भतीजावाद की राजनीति में. पिछले कुछ समय से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा तृष्टिकरण का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, इससे समाज का एक वर्ग खुद को उपेक्षित और असहाय महसूस कर रहा था. उपेक्षा और वोटबैंक की राजनीति से त्रस्त बंगाल की जनता ने तृष्टिकरण की राजनीति को खारिज़ किया है. भाजपा के कार्यकर्ता बिना थके-हारे जनता के बीच कार्य करते रहे. कार्यकर्ताओं के पास केंद्र सरकार की बहुतायत उपलब्धियों के आधार पर सोनार बांग्ला को साकार करने की नीति थी जिसको बंगाल की जनता ने स्वीकार किया. भाजपा की यह जीत कुंद हो चुकी परंपरागत राजनीति की हार है. क्षेत्रीयता की संकुचित हो चुकी राजनीति पर राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के विजय का सन्देश भी है.

भाजपा की रणनीति



कोलकाता में रोड शो के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह

त लोकसभा चुनाव में देश की नजर बंगाल पर सबसे ज्यादा थी, क्योंकि अमित शाह बार- बार यह कहते नजर आ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 22 से अधिक सीटें जीतने जा रही है. अमित शाह के इस आत्मविश्वास को

समझने के लिए 2017 में जाकर उस दौर की गतिविधियों को देखना होगा. अमित शाह ने 25 अप्रैल 2017 को नक्सलबाड़ी से अपने विस्तार अभियान की शुरुआत की थी. उस प्रवास के दौरान अमित शाह ने संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बूथ

विस्तारक, बंगाल के पत्रकार, प्रबुद्ध वर्ग सहित अनेक लोगों से संपर्क किया. शाह के प्रवास के लगभग एक साल बाद बंगाल की राजनीति ने करवट लेना शुरू किया और 2018 के पंचायत चुनाव में सात हजार से अधिक सीटें जीतकर भाजपा दूसरे नम्बर की पार्टी बनी थी. पंचायत चुनाव में आए इस परिणाम से भाजपा के हौसले बुलंद हो गए. अमित शाह यह समझ चुके थे कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है. इस दृष्टि से भाजपा ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाना शुरू किया. संघर्ष और राजनीतिक आंदोलन के द्वारा भाजपा ने धीरे -धीरे वहाँ नगण्य हो चुके विपक्ष की कमी को पूरा किया तथा लोगों को यह एहसास दिलाया कि उनकी समस्याओं को लेकर भाजपा राज्य सरकार से संघर्ष के लिए तैयार है. लगातार हो रही हिंसा की स्थिति में कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पन्ना प्रमुखों, विस्तारकों तथा सोशल मीडिया वालेंटियरों से संवाद स्थापित करना शुरू किया था. इससे कार्यकर्ता ऊर्जा एवं उत्साह के साथ पार्टी के कार्यों में जुट गये. चुनाव के दौरान भाजपा अध्यक्ष ने

ममता बनर्जी के कुशासन, एनआरसी और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर जमकर हमला किया. पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 20 सीटों को भाजपा ने चार क्लस्टर में बाँट दिया. स्पष्ट है कि जब शाह 22 सीटों पर चुनाव जीतने की बात कर रहे थे, तो वह उन 20 सीटों पर अपनी दावेदारी पक्की करने की तैयारी कर चुके थे, जिसके फलस्वरूप भाजपा ने बंगाल में 18 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है. अगर मत प्रतिशत की बात करें तो भाजपा ने 16वीं लोकसभा की तुलना में दोगुने से भी अधिक अर्थात 40.25 प्रतिशत मत प्राप्त किया है. अमित शाह ने बंगाल के चुनावी अभियान में बंगाल के हृदय को स्पर्श करने में भी सफलता प्राप्त की. एक तरफ ममता उन्हें बाहरी बताती रहीं, तो वहीँ अमित शाह बंगाल की संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के उस कालखंड का जिक्र बार-बार कर रहे थे, जब बंगाल आध्यात्मिक और साहित्यिक रूप से देश का नेतृत्व करता था. उन्होंने बंगाल की जन भावनाओं को समझते हुए उसके अनुरूप अपनी रणनीति बनाई, जिससे भाजपा ने यह अभ्तपूर्व सफलता अर्जित की.

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कथन

- आपका पसीना, आपका बलिदान, पश्चिम बंगाल के हर उस व्यक्ति को शक्ति देने वाला है, जिसकी आवाज को दशकों से दबाया गया, जिसके हक को गुंडों ने छीन लिया, जिसकी कमाई को जगाई-मथाई के गठबंधन ने लूट लिया.
- अब पश्चिम बंगाल का भाग्य और देश की दिशा भारत माता की जय कहने वाला ही तय करेगा.
- पश्चिम बंगाल के युवा नई राजनीति की शुरुआत करने वाले हैं. हिंसा, आतंक, घुसपैठ, तस्करी की राजनीतिक विरासत के साथ वे नहीं रहना चाहते. उनको नया हिन्दुस्तान चाहिए, नया पश्चिम बंगाल चाहिए. उनको एक ऐसा पश्चिम बंगाल चाहिए, जिसमें विकास की पंचधारा बहे. यानी, जहां बच्चों को पढ़ाई, युवा को कमाई, बुजुर्ग को दवाई, किसानों को सिंचाई और जन-जन की सुनवाई हो.
- मैं आपको आश्वासन देने आया हूं कि जिन घुसपैठियों को दीदी ने, टीएमसी ने अपना काडर बनाया है. उनकी चुन-चुन कर पहचान होगी, जो यहां हमारी बेटियों को परेशान करते हैं, हमारे सभ्य बंगाली मानुष को परेशान करते हैं, उनकी पहचान की जाएगी.
- वोट डालने तक के लिए यहां के मानुष को सोचना पड़ता है. राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रचार करने पर हत्या कर दी जाती है.जय श्रीराम और जय मां काली, जय मां दुर्गा के उद्घोष करने वालों को जेल तक भेजने का डर दिखाया जाता है
- अंग्रेजों की तरह दीदी भी 'भाग कोरो, शासोन कोरो' (divide and rule) की नीति पर चल रही हैं, जबिक हमारी नीति है 'ऐक कोरो, शेबा कोरो' मतलब सबका साथ - सबका विकास.

पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कथन

- बंगाल को कंगाल बनाने वाली ममता बनर्जी को हटाकर सोनार बांग्ला बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी करेंगे.
- बंगाल में लोकतंत्र को स्थापित करने में चाहें हमारी जान चली जाये, हम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित करके रहेंगे.
- जो पश्चिम बंगाल रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चन्द्र चटर्जी और डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानुभावों की धरती है, जहां कभी रवींद्र संगीत गूंजा करता था, आज वहां बम धमाकों की आवाज सुनाई देती है. बम धमाकों की आवाज में रवींद्र संगीत न जाने कहाँ गुम हो गया है.
- बड़ी वेदना के साथ यह कहना चाहता हूँ कि हम पश्चिम बंगाल की यह स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे और बदलाव लाकर रहेंगे. हम ममता बनर्जी के डर को समझते हैं, लेकिन उनका डर दूर करने का कोई रास्ता नहीं है.
- ममता बनर्जी के 7 साल के कुशासन के खिलाफ जिस तरह भाजपा ने पश्चिम

- बंगाल के हर जिले में, हर मंडल में आवाज उठाई है और इससे राज्य में जो जनजागृति आ रही है, इसी वजह से ममता बनर्जी डरी हुई है
- चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो, मूर्ति विसर्जन करना हो, कोई यात्रा निकालनी हो, कोई सभा करनी हो तो पश्चिम बंगाल में आपको न्यायालय जाना पड़ता है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन अनुमति नही देता है.
- बंगाल के एक-एक शरणार्थी से कहना चाहता हूं कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. हम यहां के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन और गोरखा शरणार्थियों को भारत का ही बेटा-बेटी मानते हैं. उन्हें यहां की नागरिकता दी जाएगी और घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा.
- यूपीए सरकार ने 13वें वित्त आयोग में बंगाल के लिए 1.32 लाख करोड़ रूपए दिए थे. मोदी जी ने 14वें वित्त आयोग में 4.24 लाख करोड़ रुपये बंगाल के विकास के लिए भेजे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ये पैसा खा गये.

ममता सरकार का भ्रष्टाचार



शारदा चिट फण्ड स्कैम: 10,000 करोड़ के शारदा चिट फण्ड स्कैम में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं का नाम शामिल है. तृणमूल के राज्यसभा सांसद कुनाल घोष शारदा के मीडिया ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे. मदन मित्रा, जो कि राज्य सरकार में खेल एंव परिवहन मंत्री थे और ममता बनर्जी के करीबी माने जाते है, उन्हें भी गिरफ्तार

किया गया था. तृणमूल के राज्यसभा सांसद श्रीन्जोय बोस और उपाध्यक्ष रजत मजुमदार को भी इस घोटाले में जेल हुई. 2011-12 में शारदा ग्रुप ने करोड़ो रूपये की साईकल, मोटरसाईकल, एम्बुलेंस का खर्चा उठाया था, जो ममता बनर्जी ने जंगलमहल और बंगाल के अन्य पिछड़े इलाकों में वितरित की थी. इसी समय राज्य सरकार ने यह भी सर्कुलर जारी किया था कि सिर्फ शारदा ग्रुप के अखबार ही सरकारी पुस्तकालयों में रखे जायेंगे. पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम का भी सीबीआई ने शारदा घोटाले की चार्जशीट में नाम दर्ज किया है. सेबी के अनुसार पूर्व केन्द्रीय मंत्री मातंग सिंह की पत्नी मनोरंजना सिंह ने सुदिप्तो सेन को नलिनी चिदंबरम से मिलवाया था.सेन का नलिनी से मिलने का उद्देश्य यह था कि सेबी और रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज के द्वारा सेन के खिलाफ जो जो जांच चल रही है, उसे प्रभावित किया जा सके. इसके लिए सुदिप्तो सेन ने अपनी कंपनी के द्वारा नलिनी चिदंबरम को 1.4 करोड़ रूपये का भुगदान भी किया था.

• रोज वैली स्कैम: यह स्कैम 17,000 करोड़ का है. इस स्कैम की जांच ED और CBI की टीम कर रही है. रोज वैली स्कैम में अब तक सुदीप बंद्योपाध्याय और तापस पाल को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीबीआई ने हाल ही में फिल्मकार श्रीकांत महतो को भी इस केस में गिरफ्तार किया है. श्रीकांत

महतो तृणमूल कांग्रेस के काफी करीबी हैं. श्रीकांत महतो को 25 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

- नारदा स्टिंग केस: नारदा स्टिंग केस में भी तथाकथित रूप से तृणमूल कांग्रेस के सुब्रता मुखर्जी, सुल्तान अहमद, सुगाता रॉय, सुवेंदु अधिकारी, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, सुवोन चटर्जी, मदन मित्रा, इकबाल अहमद घूस लेते हुए पाए गए थे.
- विवेकानंद रोड फ्लाईओवर: उत्तरी कोलकाता में विवेकानंद रोड पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर के गिरने से 27 लोगों की मृत्यु हो गयी थी. स्थानीय तृणमूल नेताओं ने निम्न श्रेणी की सामग्री उपलब्ध कराई थी जिसका पुल निर्माण में उपयोग किया गया था

कटमनी

 मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद कटमनी की बात स्वीकार की है और कटमनी का गोरखधंधा सामने आने के बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है. केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की जनता के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, पश्चिम बंगाल की सरकार और सत्ताधारी दल के नेता उसका लाभ जनता को दिलवाने के लिए कटमनी के रूप में पैसा वसूल रहे हैं. कटमनी उस रकम को कहा जाता है, जो सत्ताधारी दल के नेता सरकार की परियोजनाओं के लिए आवंटित रकम में से कमीशन के तौर पर लेते हैं.

स्थानीय लोगों का विरोध

- नादिया में टीएमसी काउंसर सोमा गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है. उनपर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलवाने के लिए 27 हजार रूपये प्रत्येक लाभार्थी से लिया हैं
- बीरभूम जिले के सिउड़ी में स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता से कटमनी वापस करने की मांग में एक सालिसी सभा यानी पंचायत का आयोजन किया था. गांव वालों से सादे काग़ज पर हस्ताक्षर कराने के बाद उन्होंने प्रति व्यक्ति 1,617 रुपए के हिसाब से 141 लोगों को इस रक्षम

का भुगतान कर दिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि एक निकासी नाला बनाने के लिए 2.28 लाख रुपए मंजूर किए गए थे. वह काम जैसे-तैसे पूरा तो हो गया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के अंचल अध्यक्ष त्रिलोचन मुखर्जी ने पूरी रक्रम हड़प ली थी. यह मामला सामने आने के बाद गाँव के लोगों ने उनका घेराव किया था. उसके बाद लोगों को बुलाकर तृणमूल नेता ने उनका पैसा वापस करना पडा.

- बर्धमान जिले के तृणमूल कांग्रेस नेता उज्ज्वल मंडल ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं, उनसे पार्टी की कल्याणमूलक गतिविधियों के लिए आम लोगों से आठ से दस हजार रुपए लिए थे.
- बर्धमान में ही इस भ्रष्टाचार के तंत्र से गुस्से में आए लोग अपना सब्र खो चुके हैं. लोगों ने कटमनी धंधे में सिक्रिय एक व्यक्ति को पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया. कटमनी के विरोध में बांकुरा में गरीब-आदिवासी महिलाए थीं, जो अपना कटमनी वापस मांग रही थीं.
- इन महिलाओं का कहना था कि

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए 5 हजार से 9 हजार तक कटमनी दिए हैं. मीडिया खबरों के मुताबिक रतनपुर ग्राम पंचायत में अभी तक 28 परिवारों के मकान बने हैं और सभी लाभार्थियों से कटमनी की वसूली की गई है, रतनपुर गांव के एक स्थानीय निवासी ने मीडिया से कहा, "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलने थे, जिसके बदले मंगल पाल ने किसी से 5 हजार, किसी से 3 हजार तो किसी से 10 हजार रुपये जबरदस्ती लिए. हमसे किश्त के नाम पर जबरदस्ती पैसे लिए इसीलिए हम थाने पर आए हैं कि हमारा पैसा हमें वापस मिले.

हर योजना का रेट फ़िक्स है

- मनरेगा में अगर किसी व्यक्ति को 100
 दिन की मजदूरी प्राप्त करनी है, तो उसके
 लिए मजदूरों को भी 56 रुपए कटमनी
 देना पडता है.
- सरकारी शौचालय का लाभ अगर आम जनता को चाहिए, तो उसके लिए 3600 रूपये लाभार्थी पहले ही कटमनी में कट जाते हैं.

- वृद्धा और विधवा पेंशन वालों से भी
 200 रुपए तक वसूलने की बात सामने
 आती रही हैं
- सरकारी आवास के लिए 5 हजार से 15 हजार तक राशि लाभार्थी को कटमनी के रूप में देनी पड़ रही है.

पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट राज

- पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में सिंडिकेट टैक्स का राज है. राज्य सरकार द्वारा आवंटित विकास कार्यों के प्रोजेक्ट से जुड़े फंड को जहाँ अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सड़क निर्माण में खर्च होना चाहिए. उस राशि से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और उसके द्वारा संरक्षित गुंडे अपनी जेब भरते हैं.
 - उदाहरण के लिए अगर आपको घर या कोई दुकान बनवाना है. इसके लिए आपको पहले पार्षद को पैसे देने पड़ेंगे. बात यहीं खत्म नही होती इस निर्माण में जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं, वह भी उन्हीं की बताई दुकानों से लेने पड़ेंगे, ऐसा नही करने पर आपके साथ हिंसा हो सकती है या आपका निर्माण कार्य रूक सकता है.

 आसनसोल और रानीगंज जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में अवैध कोयला खनन तथा निदयों से हो रहा रेत खनन बंगाल की परिस्थिति को बयां करता है.

पुलिस राज

• पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के अराजक तत्व ही सर्वेसर्वा हैं क्योंकि चाहें हिंसा हो या राजनीतिक हत्याएं हों. दोनों ही परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन बस मूकदर्शक बना रहता है और तृणमूल के अराजक तत्वों के आगे नतमस्तक रहता है. बंगाल के अन्दर तृणम्ल कांग्रेस और पुलिस प्रशासन की ज्गलबंदी चलती है और दोनों ही कानून व्यवस्था को तार-तार करने का कार्य करते हैं. राज्य में राजनीतिक हत्याएं होती हैं तो उसे पुलिस प्रशासन का संरक्षण प्राप्त रहता है, जातव्य हो कि 2019 के आम चुनाव के दौरान पूरे देश में कहीं भी हिंसा नहीं हुई और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल ऐसा एकमात्र राज्य था, जहाँ पर हर चरण में राजनीतिक हिंसा हुई. यह स्पष्ट करता है कि हिंसा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे थे. चुनावों के दौरान भाजपा के 60 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गयी, लेकिन पुलिस ने एक भी आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की. बंगाल में पंचायत चुनाव में भी भयंकर हिंसा हुई, भाजपा प्रत्याशियों पर हमले हुए और मतदाताओं को उनके मतदान अधिकार से वंचित रखने का प्रयास किया गया, परन्तु पुलिस प्रशासन सिर्फ ममता बनर्जी के आदेशों का पालन करता रहा.

- 5 सीबीआई अधिकारियों को कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के सॉल्ट लेक इलाके में स्थित घर के बाहर हिरासत में लिया गया था, जब वे चिट फंड घोटाले के मामलों की जांच के लिए वहां गए थे. तब ममता बनर्जी भी राजीव कुमार के घर पर धरना देने पहुंच गई थीं.
- कोलकाता में अमित शाह के विशाल रोड शो के दौरान पुलिस का व्यवहार ठीक नहीं था, जब टीएमसी के गुंडों द्वारा उन पर हमला किया गया और 200 साल पुरानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ी गई. उस पर भी कोलकाता पुलिस टीएमसी के अराजक तत्वों को गिरफ्तार करने के बजाय भाजपा कार्यकर्ताओं को

गिरफ्तार कर लिया.

- मार्च 2018 में पश्चिम बर्धमान के रानीगंज, उत्तर 24-परगना के काकीनाड़ा और मुर्शिदाबाद के कांडी में राम नवमी के उत्सव के दौरान हिंसा हुई, जिसमें पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठे.
- जून 2019 में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा
 3 भाजपा कार्यकर्ताओं को गोली मार दी
 गई थी और बांकुरा जिले के पंचायत में
 "जय श्री राम" के नारे लगाने पर पुलिस ने
 ममता के मन के मुताबिक़ काम करते हुए
 गोली चला दी थी. गोलीबारी के दौरान
 एक 14 साल का बच्चा भी घायल हो
 गया था.
- जब इसी तरह एक और घटना की समीक्षा करने के लिए 24 परगना के भाटपार में भाजपा प्रतिनिधिमंडल गया
 था. इस दौरान भी पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया था.

गौ तस्करी

 2016 के एक अनुमान के अनुसार भारत-बांग्लादेश सीमा पर हर दिन 3000 गायों की तस्करी होती है. राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार

और झारखंड जैसे राज्यों से सैकडों किलोमीटर की दूरी पर मवेशी खटाल नाम के बांग्लादेशी पशु बाजारों तक पहुँचते हैं. उन्हें ट्रकों में पश्चिम बंगाल के रास्ते बॉर्डर तक पहुँचाया जाता है. जानवरों की आंखों में मिर्च डालकर उन्हें ट्रकों में खड़ा रखा जाता है, जिससे जगह बने और अधिक मवेशी ले जाए जा सकें. देश के कालिंदी, इचामती, रायमंगल और हरियाभंगा नदियों के माध्यम से इन्हें ले जाया जाता है. दूरदराज के गांवों में मवेशी लोहे की जंजीरों से बंधे होते हैं और रात में युवा 'राखाल्स' या स्थानीय तैराक पानी में मवेशियों को झंड में बांधते हैं. हर राखाल्स को मिलने वाला पारिश्रमिक प्रत्येक यात्रा के लिए तीन हजार रुपये के करीब होता है. बांग्लादेश और भारत के बीच उपद्रवियों द्वारा खोदी गई गुप्त सुरंगों के द्वारा भी यह तस्करी होती है. इन घटनाओं का खुलासा दो पश् चोरों, संसुल इस्लाम और अताबुर रहमान, से पूछताछ में सामने आई, जिन्हें सीमा के भारतीय हिस्से पर पुलिस बल पर हमला करते हुए पकड़ा गया था. इन तस्करों ने स्वीकार किया कि वह भारत

में स्थित करीमगंज गुप्त मार्ग (सुरंग) से प्रवेश करते हैं. पशु की तस्करी के इन तरीकों के अलावा तस्कर पशु के पैरों में भारी लकड़ी के लॉग भी बांधते हैं और पड़ोसी देश के तट तक पहुंचने के बाद नदी के पार से आगे बाजारों तक ले जाते हैं. इससे कई गायों की मौके पर ही मौत हो जाती है. तस्करों के इन वक्तव्यों के उपरांत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में इनका जाल सक्रीय है.

- इस पशु तस्करी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) को इस समस्या से निपटने के लिए निर्देश भी दिए हैं. भारत और बांग्लादेश के तस्कर एक-दूसरे के साथ सांठगांठ कर जुड़े हुए हैं और सीमा पर गश्त करने वाले सुरक्षा बलों के स्थान के बारे में जानकारी भी रखते हैं. ऐसे भी उदाहरण हैं जब तस्करों की संख्या बीएसएफ के जवानों से अधिक होती है. कभी-कभी गौ-तस्कर भी कच्चे बम या घरेलू पिस्तौल से लैस होते हैं.
- यद्यपि बीएसएफ की तकनीकों में उन्नति

के कारण पशु तस्करी में कमी आई है. केन्द्र सरकार ने सीमा पर एक बड़ी सैन्य टुकड़ी की भी मंजूरी दी है. इसका असर भी हुआ है. आंकड़ों के मुताबिक 2014 में 1,53,602, 2015 में 1,68,801 और 2017 में 30,99,744 मवेशियों को सीमा सुरक्षा बलों द्वारा तस्करों के पास से जब्त किया गया है.

जाली नोट

• पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में 7 लाख रूपए के जाली नोट जब्त किए गए थे और 26 मई 2019 को इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. मानिकचक पुलिस स्टेशन के तहत इनायतपुर में एक नकली मुद्रा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया. गिरफ्तार व्यक्ति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का निवासी थे. पुलिस ने उसके पास से उच्च गुणवत्ता के नकली भारतीय मुद्रा नोट (FICN) जब्त किए थे. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जाली नोटों पर कोई कार्यवाही नहीं करती है.

जनविरोधी ममता सरकार

रकार का मूल काम जनकल्याण का होता है. सरकार का यह दायित्व होता है कि वह अपने राज्य की जनता की चिंता करे. उनकी समस्याओं का निराकरण कर उन्हें विकास के पथ पर अग्रसर करे, किन्तु पश्चिम बंगाल में इसके उलट हो रहा है. मुख्यमंत्री की तानाशाही, तुष्टिकरण और जनविरोधी नीतियों से समाज के एक बड़े वर्ग में नाराजगी है. इन समस्याओं को लेकर जब कोई आवाज उठती है, तब ममता बनर्जी सत्ता का दुरूपयोग करते हुए उन पर कार्यवाही करती हैं.

ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की कमी

पश्चिम बंगाल का ग्रामीण इलाका डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है. सरकार को अभी भी डर है कि अगर ट्रेनी रिज़र्व डॉक्टर, एमबीबीएस में पास होने वाले कुल डॉक्टरों का 10%, जो राज्य सरकार के अस्पतालों में काम करते हैं, वो अगर छुट्टी पर चले जाते हैं तो राज्य की चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी. वर्तमान में पश्चिम बंगाल

में 923 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हैं और इन प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में 918 डॉक्टर हैं. इन डॉक्टरों में से अधिकांश वो हैं जो अपनी एमबीबीएस पूरी कर चुके हैं और सरकार के साथ 3 साल के अनुबंध पर काम कर रहे हैं. हर स्वास्थ्य केंद्र में 5 डॉक्टर आवश्यक रूप से होने चाहिए, लेकिन अभी अधिकांश केन्द्रों में 1 डॉक्टर से काम चलाया जा रहा है. राज्य की चिकित्सा व्यवस्था निश्चित रूप से चरमरा गई है.

 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वास्थ्य मिशन है, जिसका लक्ष्य देश में सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है, लेकिन बंगाल सरकार ने इसे ढंग से अमल नहीं किया. सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) मानदंड के अनुसार राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहा है, जिसमें पानी की आपूर्ति, बिजली, आदि जैसी समस्याएँ हैं. IPHS के मानदंड के अनुसार हर स्तर पर डॉक्टरों, नर्स और अन्य सहायक कर्मचारियों की कमी देखी गई.

हावड़ा में वकीलों पर हमला

24 अप्रैल 2019 को हावड़ा जिला न्यायालय में पार्किंग को लेकर नगर निगम के कर्मचारियों और वकीलों में हुई मामूली बहस के बाद जितने भी वकील वहाँ उपस्थित थे, उनपर पुलिस ने लाठी-डंडो से प्रहार किया. स्थानीय पुलिस ने महिलाओं को भद्दी-भद्दी गालियाँ भी दीं. उसके बाद से लगभग 55 हजार वकीलों ने अपना काम रोक दिया, जिससे बंगाल की समूची न्याय व्यवस्था उप्प पड़ गई थी. यह हड़ताल एक महीने तक चली . सुप्रीमकोर्ट ने इस घटना के सदर्भ में टिप्पणी करते हुए इसे 'असाधारण' बताया था.

साबर जनजाति की त्रासदी

नवंबर, 2018 में साबर जनजाति के 7 लोगों की भूखमरी के चलते मृत्यु हो गयी थी. यह घटना पश्चिमी मेदिनापुर के लालगढ़ में हुई थी, जो जनजातीय इलाका है. ममता बनर्जी ने इस घटना को ही सिरे से नकार दिया था. ममता बनर्जी सरकार ने नार्थ 24
परगना के बारासात के सरकारी
अस्पताल में काम कर रहे एक
डॉक्टर अरुणाचल दत्त चौधरी को
सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया,
क्योंकि डाक्टर ने फेसबुक पर डेंगू
के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता
जाहिर की थी.

उन्होंने कहा था कि ये मृत्यु भूखमरी के कारण ना होकर बल्कि बुढ़ापे और शराब के सेवन के कारण हुई है. तृणमूल सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि लोगों का इस मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके.

बंगाल में डेंगू से मौतें

 पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने नार्थ 24 परगना के बारासात के सरकारी अस्पताल में काम कर रहे एक डॉक्टर अरुणाचल दत्त चौधरी को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया, क्योंकि डाक्टर ने फेसबुक पर डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर चिंता जाहिर की थी. यह मामला नवम्बर 2017 का है. डॉक्टर ने कहा था कि ममता सरकार डेंगू से जुड़े मामलों को दबाने का प्रयास कर रही है. उनका यह भी कहना था कि राज्य सरकार डाक्टरों पर यह दबाव बना रही है कि डेंगू के चलते जिनकी मृत्यु हो रही है, उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पर डेंगू का जिक्र ना करके किसी और बीमारी का उल्लेख हो, जिससे सरकार डेंगू से मरने वालों का आकड़ा छुपा सके. बर्खास्तगी के विरोध में पांच सौ डाक्टरों ने रैली भी निकाली थी, जिन्हें पुलिस ने स्वास्थ्य भवन के पास ही रोक लिया.

 इसके अलावा नार्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अधीक्षक डॉ अनूप रॉय को भी राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई बयाँ करने के कारण सस्पेण्ड कर दिया गया था. गौरतलब है कि उस समय राज्य गंभीर इन्सेफेलाइटिस के प्रकोप से गुजर रहा था.

विद्यार्थियों पर पुलिस फायरिंग

सितम्बर, 2018 में पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में दिश्मित हाईस्कूल में विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा उर्दू शिक्षक की नियुक्ति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो पुलिस ने विद्यार्थियों पर फार्यारंग शुरू कर दी. पुलिस की फायरिंग में राजेश सरकार और तापस बर्मन नाम के विद्यालय के दो पूर्व छात्रों की मृत्यु हो गयी थी. एक दर्जन से भी अधिक लोग इस घटना के दौरान घायल हो गए थे. गौरतलब है कि इन छात्रों की मांग बांग्ला शिक्षक की नियुक्ति की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बांग्ला की जगह उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई.

मेडिकल छात्रों के मांगों की उपेक्षा

जुलाई, 2018 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, क्योंकि उनके हॉस्टल में उन्हें आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही थी, विद्यार्थियों का कहना था कि सिर्फ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ही नए हॉस्टल में कमरे उपलब्ध कराये गए हैं. जिस पुराने हॉस्टल में विद्यार्थी रह रहे थे, उस बिल्डिंग की हालत खस्ता थी.

 हॉस्टल में खाने और पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी, उस बिल्डिंग की छत को रिपेयर करवाने की सख्त आवश्यकता थी क्योंकि छत के गिरने के कारण पहले भी एक विद्यार्थी घायल हो चुका था. विद्यार्थी पिछले 3 सालों से नए हॉस्टल के आवंटन का इंतजार कर रहे थे.

• प्रधानाचार्य के कमरे के सामने हड़ताल कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया तथा टीएमसी के गुंडों ने भी छात्रों से मारपीट की थी. अपने हक के लिए दो सप्ताह तक प्रदर्शन कर रहे छात्रों को कॉलेज प्रशासन ने 'माओवादी' तक करार दे दिया था. कॉलेज प्रशासन छात्रों की मांगों की उपेक्षा कर, सरकार के समर्थन में खड़ा दिखा.

पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर त्रासदी

जून, 2019 में कोलकाता स्थित एनआरएस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक रोगी की मौत के बाद जूनियर डॉक्टरों के साथ मृतक के परिजनों की हुई मारपीट की घटना के बाद राज्य के साथ-साथ पूर्व एवं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की स्वास्थ्य परिसेवा भी ठप हो गई थी. इस घटना के बाद बंगाल सहित पूरे देश के डॉक्टरों ने इसका विरोध किया और हड़ताल पर चले गए, जिस कारण लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

 जूनियर डॉक्टरों का कहना था कि जब तक उनकी सुरक्षा और अन्य मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे यहाँ सरकार और डॉक्टरों के बीच जो टकराव देखने को मिला वह राज्य सरकार के लिए शर्म की बात है. ममता के अड़ियल खैये के कारण समूचे देश का स्वास्थ्य महकमा ठप्प पड़ गया था. जिससे सबसे अधिक परेशान आम जनता हुई. ममता बनर्जी को चाहिए था कि वे चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करतीं. इससे डॉक्टर काम पर वापस लौटते और मरीजों को इलाज की सुविधा जल्द प्राप्त होती, लेकिन ममता बनर्जी डॉक्टरों से हमदर्दी की जगह उन्हें धमकी देने लगीं और गुस्से में कहने लगी कि किसी घटना में पुलिस वाले की मौत होने पर उनके साथी क्या हडताल करते हैं ? यह अजीबोगरीब बयान था. उन्होंने यह भी कहा अगर डॉक्टर काम पर नहीं लौटे तो उनसे हॉस्टल खाली करवा लिया जाएगा. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धमकी भरे लहजे में जूनियर डॉक्टरों को जल्द से जल्द काम पर लौटने को कहा और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह चार घंटे के अंदर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

- ममता ने हड़ताली डॉक्टरों को भी बाहरी बता दिया और कहा कि जो यहां की स्थिति को और खराब कर रहे हैं, वह बाहरी लोग हैं. उन्होंने पुलिस को स्थिति से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. ममता बनर्जी के इस रवैये के बाद डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला आरंभ हो गया, लेकिन इसपर भी ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल बीजेपी की साजिश है.
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता देखिये कि बंगाल में बिगड़े हालातों पर बातचीत के लिए जब राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी ने उन्हें फोन किया तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला. गवर्नर ऑफिस से मुख्यमंत्री दफ्तर संदेश तक पहुंचाया गया कि राज्यपाल मिलना चाहते हैं, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोई जवाब नहीं आया.
- इसके बाद जब केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री
 डॉ. हर्षवर्धन ने ममता से संपर्क करने की कोशिश की तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.
- इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी ममता सरकार को फटकार लगाई और पूछा कि डॉक्टरों से गतिरोध खत्म करने

ममता ने हड़ताली डॉक्टरों को भी बाहरी बता दिया और कहा कि जो यहां की स्थिति को और खराब कर रहे हैं, वह बाहरी लोग हैं. उन्होंने पुलिस को स्थिति से निपटने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. ममता बनर्जी के इस रवैये के बाद डॉक्टरों के इस्तीफे का सिलसिला आरंभ हो गया, लेकिन इसपर भी ममता बनर्जी ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल बीजेपी की साजिश है.

के लिए क्या कदम सरकार ने उठाए. डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ममता सरकार ने क्या किया है? हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता बंगाल में हालात संभालने की होनी चाहिए थी, उस वक्त वह इस मामले में राजनीतिक लाभ-हानि देख रही थीं. बंगाल में 600 से ज्यादा डॉक्टर्स इस्तीफा दे चुके थे. बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर थे तथा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने जानबूझकर स्थिति को बिगड़ने दिया.

पश्चिम बंगाल कैडर के रिटायर्ड आईपीएस
 अफ़सर गौरव दत्त ने 19 फ़रवरी 2019

को नस काट कर आत्महत्या कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में इस कदम के लिए ममता बनर्जी को ज़िम्मेदार ठहराया था. गौरव दत्त 1986 बैच के अफ़सर थे. दत्त ने पिछले साल ही सेवा से स्वैच्छिक अवकाश ले लिया था. सुसाइड नोट में दत्त ने लिखा है कि उनकी मौत के लिए पूरी तरह ममता बनर्जी ज़िम्मेदार हैं.

- 2016 में स्कूल सर्विस कमीशन का परीक्षा पास करने के बावजूद उनकी भर्ती नहीं की गई और उन्हें वेटिंग लिस्ट में रखा गया. अभ्यर्थियों ने 600 घन्टे तक अनशन किया. उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा.
- अगर शिक्षा की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2016-17 के अनुसार लगभग 27 प्रतिशत स्कूल यानी 2362 स्कूल ऐसे हैं, जो हेडमास्टर/प्रिंसिपल के बिना संचालित हो रहे हैं.

महिला विरोधी ममता सरकार

 केंद्र सरकार की जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत डिलीवरी होने पर मां के बैंक खाते में 6 हजार रूपए दिए जाते हैं, लेकिन

- बंगाल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण किसी को 600 तो किसी को 300 रूपए मिल रहे हैं.
- पश्चिम बंगाल में महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम मातृत्व लाभ मातृ वंदना योजना और वन स्टाप सेंटर योजना को लागू नहीं किया गया है.
 - नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में घरेलू हिंसा के मामलों में बेतहाशा बढोत्तरी हुई है.वर्ष 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा मामले में पश्चिम बंगाल सबसे आगे चल रहा है. 2015 में जहां राज्य में 20,265 महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हुई; वहीं 2016 में यह आंकड़ा 34,205 तक पहुंच गया.
 - 2016 की एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में मानव तस्करी के 44% मामले केवल पश्चिम बंगाल से आते हैं. मानव तस्करी की बात आते ही बंगाल की महिलाएं और लड़िकयां सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं. इन सब के बावजूद ममता बनर्जी ने इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया.
- पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए

असुरक्षित राज्य बना हुआ है. पिछले आठ वर्षों से लगातार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं, जो टीएमसी के माँ-माटी-मानुष के नारे को झठलाती हैं. जैसे कि फ़रवरी 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामला, जिसमें दो बच्चों की माँ सुजेट जॉर्डन (37) के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. इसी तरह जून 2013 में कामदुनी में सामूहिक बलात्कार की घटना घटी थी, जिसमें 19 वर्षीय छात्रा शिप्रा घोष के साथ गैंगरेप के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी. इन घटनाओं ने देश की अंतरात्मा को हिला कर रख दिया था, किन्तु इन मौकों पर ममता बनर्जी ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा कि ये उन्हें बदनाम करने की साजिश थी. पार्क स्ट्रीट मामले में तो उन्होंने कहा कि यह ''मनगढ़ंत" (सजानो- घाटाना) था. कामदुनी मामले उन्होंने कार्यवाही का भरोसा दिया था. लेकिन जब उन्हें पता चला कि यह उनका ही गढ़ है तथा इस गैंगरेप से जुड़े आरोपी भी उन्हीं की पार्टी से संबंध रखते हैं. तो वह अपनी बात से पीछे हट गईं. ऐसे अधिकांश अपराधों में यह देखा जाता है कि अपराधी एक

विशेष समुदाय का होता है तथा स्थानीय टीएमसी नेताओं के पक्ष का होता है.

- ममता बनर्जी का यह व्यवहार 1990 में हुए बंटाला गैंग रेप केस पर ज्योति बस् की प्रतिक्रिया की याद दिलाता है, उस वर्ष 30 मई को टीकाकरण के कार्यक्रम को खत्म कर, कोलकाता वापस रहीं 3 महिला स्वास्थ्य अधिकारियों को बंटाला में जबरन रोक कर उनके ड्राइवर को मार दिया गया. उसके बाद उन महिलाओं को खेतों में ले जाकर, उनके साथ बलात्कार किया गया तथा बेरहमी से मार दिया गया उन महिलाओं में से एक महिला, अनिता द्वान यूनिसेफ की अधिकारी थीं. इस मामले पर कॉमरेड बस् ने कहा था, 'वे वहां क्यों गई थीं? ऐसी घटनाएं होती रहती हैं'. इस घटना में स्थानीय सीपीआईएम के गुंडे भी शामिल थे
- पश्चिम बंगाल को मातृ शक्ति की आराधना का स्थल कहा गया है, लेकिन आज यहां महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं. गौरतलब है कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद ममता बनर्जी महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल और असंवेदनशील रही हैं.

तृणमूल की तानाशाही

अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला

पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक जीवन की मर्यादाओं को ताक पर रख दिया है. उनके बयान, उनकी कार्यशैली में तानशाही की झलक दिखती है, चाहे राजनीतिक हिंसा हो, भाजपा नेताओं की रैली में खलल डालने की बात हो, पंचायत चुनाव में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा लोकतंत्र पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो अथवा जय श्रीराम के नारे से परहेज करना हो, ऐसे सैकड़ो उदारहण मिल जाएंगे, जहाँ ममता ने अपनी तानाशाही दिखाई.

फिल्म बैन

फरवरी 2019 में अनिक दत्ता के निर्देशन
में बनी 'भोबिश्यतेर भूत' फिल्म रिलीज
होने के दो दिन बाद ही बिना कुछ बताएं
सिनेमाघरों से हटा दी गई. लोगों का
यह कहना था कि यह फिल्म बंगाल की

वर्तमान स्थिति को प्रतिबिंबित कर रही थी. अत: जैसे ही इस फिल्म के बारे में राज्य सरकार को पता चला, उसने उसे सिनेमाघरों पर दबाव बनाकर हटावा दिया, जिसके विरोध में बांग्ला सिनेमा के कई जाने-माने चर्चित चेहरे सामने आए. मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद से कोर्ट ने राज्य सरकार को तीखी फटकार सुनाई और बीस लाख का जुर्माना भी लगाया.

2013 में फिल्म निर्माता सुमन मुखोपाध्याय की बंगाली फिल्म कंगाल मलसाट को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय निकाय द्वारा पारित नहीं किया गया था. यह फिल्म पश्चिम बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ गरीबों के विद्रोह के बारे में थी. फ्लाईओवर और मॉल जैसे शहरी बुनियादी ढांचे और उद्योग पर वामपंथियों के ध्यान न देने की कमी के बारे में थी. इस फिल्म के अंतिम सात मिनटों में तृणमूल सरकार की नाकामियों को भी दर्शाया गया है और इसी कारण ममता ने पूरी फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था.

जय श्रीराम के नारों से ममता बनर्जी को इतनी दिक्कत क्यों है ?

5 मई को घटाल लोकसभा क्षेत्र से गुजर रही ममता बनर्जी ने जय श्रीराम के नारे लगा रहे ग्रामीणों को देखकर उनपर भड़क उठीं और कहने लगीं कि इधर आओ कहाँ भाग रहे हो, तुम मुझे गाली देते हो? अब समझा जा सकता है कि ममता की न्यूनतम सोच क्या है, जय श्रीराम गाली हो सकती है क्या?

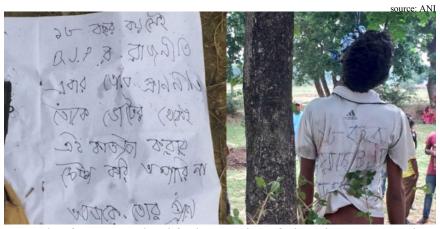
• बौखलाई ममता ने जय श्रीराम का नारा लगाने के आरोप में 7 लोगों को हिरासत में ले लिया. ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति में इस कदर रम गयी हैं कि अब उन्हें बंगाल में जय श्रीराम और सरस्वती पूजा से भी तकलीफ हो रही है. इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसमें नारे लगाने वालों को वह क्रिमिनल कहती नजर आ रही हैं. पश्चिम बंगाल में अगर किसी राम भक्त ने जय श्रीराम का नारा लगाया तो वह ममता बनर्जी को रास नहीं आता है. जय श्रीराम के नारे सुनकर ममता बनर्जी ने कहा था कि 'बीजेपी के गुंडों,

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और प्रियंका को रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद भी ममता सरकार ने प्रियंका शर्मा को तय समय पर नहीं छोड़ा, जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर अवमानना का नोटिस जारी किया है.

यहाँ पर तुम लोग हमारे कारण रह रहे हो , तुम सारे लोग बदमाश हो, तुम जैसे लोगों को मै भगा भी सकती हूँ, मैं तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ दूंगी'. अब सवाल यह है कि जय श्रीराम बोलने वाले लोग आतंकी हैं? अपराधी हैं? जिन्हें घरों से निकालकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा.

कार्टून से बिफरी हिटलर दीदी

लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता दीदी के राज में पश्चिम बंगाल के एक प्रोफेसर की गिरफ़्तारी कर ली गयी थी. यह महज इसलिए हुआ था क्योंकि जाधवपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा ने इंटरनेट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संबंधित कार्टून



भाजपा के दलित युवा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो की निर्ममता से हत्या कर दी गई थी.

शेयर कर दिया था. ज्ञातव्य हो कि महापात्रा ने बताया कि केवल मजे के लिए उन्होंने कार्टून अपने दोस्तों को भेजा था, लेकिन पहले तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी और फिर उन्हें हवालात में बंद कर दिया. तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी का समर्थन किया पश्चिम बंगाल के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा कि इस तरह की किसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं श्रममंत्री पूर्णेंद् बसु ने कहा कि 'यह ममता बनर्जी का अपमान कर उनकी छवि पर बट्टा लगाने का प्रयास है. ऐसे मामलों में पुलिस ने जो किया वह बिल्कुल सही है.' यह गिरफ़्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के न्यूनतम लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला है. इस तरह की घटनाएँ दर्शाती हैं

कि ममता बनर्जी एक व्यंग्य भी सहन करने की स्थिति में नहीं है और पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की आवाज दबाने पर अमादा हैं.

मीम से भी ममता को परहेज़

भाजपा युवा मोर्चा से जुडी प्रियंका शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर किया था.यह तानाशाही की पराकाष्ठा ही है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यातना दी. जब मामला सुप्रीमकोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई और प्रियंका को रिहा करने का आदेश दिया. इसके बाद भी ममता सरकार ने प्रियंका शर्मा को तय समय पर नहीं छोड़ा, जिसके बाद कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है.

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा

श्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते प्रभाव और राज्य की जनता द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को लेकर बढते विश्वास को देखकर ममता बनर्जी और तृणम्ल कांग्रेस घबराहट में हैं, घबराहट में बेबुनियाद बयान देते हुए ममता बनर्जी कहती है 'हिंसा के लिए अमित शाह जिम्मेदार हैं, मैं यहां शांत बैठी हूं. वरना एक सेकेंड में दिल्ली में भाजपा दफ्तर और तुम्हारे घरों पर कब्जा कर सकती हूं.' अतः यह दर्शाता है कि हिंसा का माहौल कौन बना रहा है और वह कौन-सी सरकार है, जो सत्ता में होने के बावजुद पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था को नहीं संभाल पा रही है. यह राजनीतिक हत्याएं उस दौर की याद दिलाती हैं, जब कम्युनिस्ट सरकार द्वारा मुख्य रूप से अपने विरोधियों को निशाना बनाया जाता था, लेकिन आज बंगाल की जो स्थिति है वह कम्युनिस्ट सरकार के कार्यकाल से भी अधिक भयावह व गंभीर है. तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पश्चिम बंगाल को हिंसा का केन्द्र बना दिया है, जहाँ सिर्फ ममता बनर्जी के

समर्थक ही सुरक्षित हैं और विरोधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है. ममता बनर्जी के राज में लोकतांत्रिक मूल्य ध्वस्त हो चुके हैं और संवैधानिक व्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है. गौरतलब है कि 2014 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की 42 में से 2 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके बाद धीरे-धीरे भाजपा के बढते प्रभाव से हताश ममता बनर्जी ने हिंसा को ही प्राथमिकता दी. हाल ही में संपन्न हुए 2019 के आम चुनावों में तो यह राजनीतिक हिंसा चरम पर थी और मतदान का कोई भी चरण ऐसा नहीं रहा, जिसमें तृणमूल के गुंडों द्वारा भाजपा के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं पर हमले नहीं हुए हों. ज्ञातव्य हो कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के रोड शो में आगजनी, तोड़फोड़ हुई. खुद भाजपा अध्यक्ष ने इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यदि केन्द्रीय सुरक्षा बल उनके रोड शो के दौरान मौजूद नहीं होता, तो उनका वहां से बच निकलना मुश्किल था. यह स्थिति स्पष्ट करती है कि बंगाल की ममता सरकार किस

कदर भाजपा के नेताओं के प्रति नफरत की भावना रखती है. इसके अतिरिक्त चुनावों के दौरान भाजपा नेताओं की सभाओं की अनुमति नहीं देना, उनके हेलिकॉप्टर नहीं उतरने देना. यह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हताशा को दिखाता है

पश्चिम बंगाल में हुई मुख्य राजनीतिक हिंसाओं का विवरण

रामबाबू शॉ और धर्मेंद्र शॉ की हत्या 20 जून, 2019

20 जून को उत्तर 24 परगना जिले के भाटापारा में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने झड़प होने पर दो बीजेपी कार्यकर्ताओं रामबाबू शॉ और धर्मेंद्र शॉ की गोली मारकर हत्या कर दी.

आनंद पाल की हत्या

18 जून, 2019

पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी की गुंडा ब्रिगेड ने एक और भाजपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी. 18 जून को 28 साल के आनंद पाल का गला रेतकर बेरहमी से मार डाला.

सरस्वती दास की हत्या

13 जून, 2019

बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के हासनाबाद में महिला भाजपा कार्यकर्ता की सिर में गोली

मारकर हत्या कर दी गई. अमलानी पंचायत में 42 साल की सरस्वती दास पर टीएमसी के गुंडों ने ताबडतोड फायरिंग की थी.

अनिल सिंह की हत्या

11 जून, 2019

भारतीय जनता पार्टी के सिक्रय कार्यकर्ता अनिल सिंह दो दिनों तक मालदा इलाके से लापता थे. बताया जा रहा है कि इंग्लिश बाजार इलाके में खासे लोकप्रिय भाजपा नेता अनिल सिंह का टीएमसी के गुंडों ने अपहरण कर लिया था और फिर उनकी पीट-पीट कर हत्या कर दी. अनिल सिंह का शव इंग्लिश बाजार इलाके के बाधापुकुर में मिला था. उनके शव पर चोट के निशान थे.

स्वदेश मन्ना की हत्या

9 जून, 2019

हावड़ा के भाजपा कार्यकर्ता स्वदेश मन्ना का शव अतचटा गांव में पेड़ से लटकते हुए मिला. बताया जा रहा है कि स्वदेश मन्ना ने कुछ दिन पहले स्थानीय स्तर पर 'जय श्रीराम रैली' निकाली थी. इसी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे. स्थानीय लोगों के मुताबिक टीएमसी के गुंडों ने स्वदेश मन्ना को पीट-पीट कर मार डाला और फिर उनका शव पेड़ से



पंचायत चुनाव में अराजक तत्वों ने मालदा में मतपेटियों को आग के हवाले कर दिया

लटका दिया.

समतूल दूलूई की हत्या 9 जून, 2019

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समतूल दूलूई की हत्या भी 'जय श्रीराम' का नारा लगाने के चलते कर दी गई. एक स्थानीय कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता समतूल दूलूई ने कई बार जय श्रीराम का नारा लगाया था, जिससे वहां मौजूद टीएमसी के नेता नाराज हो गए. रात में टीएमसी के गुंडों ने दूलूई को घर से अगवा कर लिया और पीट-पीट कर हत्या कर दी. इतना ही नहीं टीएमसी के गुंडों ने दूलूई के

शव को पेड़ से लटका दिया था. दूलूई बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता थे और उन्होंने अपने बूथ में लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को बढ़त दिलाई थी. चुनाव के तुरंत बाद तृणमूल के लोगों द्वारा दूलूई के घर पर तोड़फोड़ भी की गई थी.

सुकांता मंडल, प्रदीप मंडल और तपन मंडल की एक साथ हत्या

8 जून, 2019

पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में 8 जून, 2019 की रात को तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बशीरहाट इलाके के संदेशखाली में भाजपा

पश्चिम बंगाल परिवर्तन की ओर

कार्यकर्ताओं को घेर लिया और उन पर बम व गोलियों से हमला बोल दिया. टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के इन तीनों कार्यकर्ताओं की आंखों में गोली मारकर हत्या कर दी

तन्मय संत्रा की हत्या

3 जून, 2019

विष्णुपुर लोकसभा क्षेत्र के टीएमसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा के झंडे बांधने के लिए तन्मय संत्रा की हत्या कर दी

अजय मंडल की हत्या

2 जून, 2019

उत्तर 24 परगना के बशीरहाट इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता अजय मंडल की 2 जून को चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई. बादुड़िया निवासी अजय मंडल ने लोकसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस से नाता तोड़ कर भाजपा का दामन थामा था

सुशील मंडल की हत्या 30 मई, 2019

लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ घंटे पहले बंगाल के पूर्वी बर्धवान जिले के केतुग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता सुशील मंडल (52) की हत्या कर दी गई. सुशील मंडल की

पत्नी के मुताबिक जय श्रीराम का नारे लगाने से नाराज टीएमसी के लोगों ने उनके पति की हत्या की है.

चंदन शॉ की हत्या

27 मई, 2019

पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के भाटापारा में 27 मई को भाजपा कार्यकर्ता चंदन शॉ की हत्या कर दी गई. राजनीतिक रंजिश में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रात साढ़े दस बजे घर लौटते हुए चंदन पर बम से हमला कर उनकी हत्या कर दी.

शान्तनु घोष की हत्या

24 मई, 2019

25 साल के शांतनु घोष को तृणमूल छोड़ भाजपा में जाने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है. भाजपा कार्यकर्ता शान्तनु घोष की हत्या उत्तरी चौबीस परगना के काकीनारा में हुई. शान्तनु घोष 24 मई को टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे.

जयदेब बर्मन की हत्या

21 मई, 2019

कूचिबहार में टीएमसी के गुंडों ने भाजपा नेता जयदेब बर्मन की एके-47 से गोली मारकर हत्या कर दी.

हरधन मृधा की हत्या 17 मई, 2019

कृष्णानगर लोकसभा सीट पर 46 वर्षीय भाजपा कार्यकर्ता हरधन मृधा की तृणमूल के गुंडों की हत्या कर दी.

रमन सिंह की हत्या

11 मई, 2019

लोकसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के झारग्राम लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक रंजिश में भाजपा वर्कर रमन सिंह(30) की सिर पर लोहे की रॉड मारकर हत्या कर दी.

शिशुपाल सहिस की हत्या

18 अप्रैल, 2019

पुरुलिया में भाजपा के ग्राम पंचायत सदस्य 22 वर्षीय शिशुपाल को टीएमसी के गुंडों ने पेड़ पर फांसी लगा दी और उनकी हत्या कर दी.

नित्य मंडल की हत्या

4 अप्रैल, 2019

सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली के एक दिन बाद टीएमसी के गुंडों ने भाजपा कार्यकर्ता नित्य मंडल (42) को भाजपा के बूथ ऑफिस में फांसी पर लटका दिया

पतन् मंडल की हत्या

29 मार्च, 2019

आज बंगाल की जो स्थिति है, वह कम्युनिस्ट सरकार के कार्यकाल से भी अधिक भयावह व गंभीर है. तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने पश्चिम बंगाल को हिंसा का केन्द्र बना दिया है.

मालदा के हिरिश्चंद्रपुर क्षेत्र दौलतपुर में भाजपा कार्यकर्ता पतनू मंडल की टीएमसी के लोगों ने उस वक्त हत्या कर दी, जब वो सो रहे थे.

हिंसा की अन्य घटनाएँ

- पश्चिम बंगाल के निदया जिले में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्ण देवनाथ की 'जय श्री राम' का नारा लगाने पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीट-पीट कर हत्या कर दी.
- 1 जून, 2019 को पश्चिम बंगाल के बलरामपुर में 32 वर्षीय दुलाल कुमार को मार दिया गया. इस हत्या की आशंका पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने स्वयं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अनुज शर्मा से व्यक्त की थी. बावजूद इसके दुलाल की हत्या न सिर्फ पुलिस प्रशासन की नीयत पर सवाल खड़े करती है, बल्कि सत्ताधारी दल की सहमति भी बयां कर रही है.

- 2019 के आम चुनावों के संपन्न होने के बाद भी भाजपा कार्यकर्ताओं पर निरंतर हमले जारी हैं. हाल ही में झाड़ग्राम के जामबनी में शाम को कीर्तन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता खगपित महतो की हत्या कर दी गयी. परिजनों ने कहा है कि भाजपा में शामिल होने के कारण खगपित महतो की हत्या कर दी गयी थी.
- पश्चिम बंगाल के दमदम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सिमक भट्टाचार्य के कार्यालय पर तोड़फोड़ की गई. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए.वहाँ कुर्सियां तोड़ दी गई थी और जिला सिचव को बुरी तरह पीटा गया था.
- 2019 के आम चुनावों में चौथे चरण के मतदान के दौरान आसनसोल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सुरक्षाबलों के साथ झड़प की. यही नहीं बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो की कार का शीशे भी तोड़ दिया गया. इस सियासी हिंसा में सरेआम कानून की धिज्जयां उड़ाई गईं और पुलिस तमाशाबीन बनी रही. बंगाल में तैनात किए गए विशेष चुनाव पर्यवेक्षक अजय वी नायक को इस स्थिति पर कहना पड़ा कि 'राज्य पुलिस पर लोगों को भरोसा नहीं है '

- छठे चरण में मतदान के दौरान घाटल से भाजपा प्रत्याशी भारती घोष पर हमला किया गया और इसी चरण की वोटिंग के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष पर भी हमले की कोशिश हुई थी.
- 54 वर्षीय धर्मराज हजरा की लाश शिक्तपुर गाँव में एक झील में मिली थी. धर्मराज हजरा भाजपा की मंडल कमेटी के सदस्य थे और उन्हें पंचायत चुनाव से ही भाजपा के समर्थन के लिए जान से मारने की धमिकयां मिल रही थीं.
 - धर्मराज हजरा से पहले भी पुरुलिया के दिलत त्रिलोचन महतो और दुलत कुमार को मौत के घाट उतार दिया गया था. तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने सारी हदों को पार करते हुए भाजपा के दिलत युवा कार्यकर्ता की न केवल निर्मम हत्या की और उसके शव को पेड़ में लटका दिया. उसके टीशर्ट तथा हत्या की जगह से बरामद एक नोट पर लिखा था कि '18 साल की उम्र में बीजेपी के लिए काम करोगे तो यही हश्र होगा' यह नफ़रत से भरी हुई राजनीति का रक्तरंजित चेहरा है. त्रिलोचन महतो का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिला था और दुलत कुमार की लाश एक हाई टेंशन पोल से लटकी हुई

मिली थी. इससे पूर्व अप्रेल,2018 के महीने में भी तृणमूल कार्यकर्ताओं के द्वारा बांकुरा के रानीबाग में की गयी हिंसा में अजीत मुर्मू ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था. अजीत मुर्मू भाजपा की तरफ से पंचायत चुनाव में उम्मीदवार थे.

- 2019 लोकसभा चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने पर बीजेपी समर्थकों की तरफ से बीरभूम में निकाली गई 'विजय रैली' के दौरान बम फेंका गया था.
- पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की 713 कंपनियां और 71 हजार सुरक्षाकर्मियों की तैनाती के बावजूद हिंसक घटनाएं नहीं थमीं. 2019 के हर चरण के चुनाव संपन्न होने के साथ-साथ राजनीतिक हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती गईं.
- 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी पश्चिम बंगाल में खूब हिंसा हुई थी. सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस दौरान 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1100 से ज्यादा राजनीति हिंसा की घटनाएं राज्य में चुनाव के दौरान दर्ज की गई थी.
- एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार वर्ष
 2016 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से झड़प की 91 घटनाएं हुईं और 205 लोग

हिंसा के शिकार हुए. इससे पहले यानी वर्ष 2015 में राजनीतिक झड़प की कुल 131 घटनाएं दर्ज की गई थीं और 184 लोग इसके शिकार हुए थे. वर्ष 2013 में बंगाल में राजनीतिक कारणों से 26 लोगों की हत्या हुई थी, जो किसी भी राज्य से अधिक थी.

गृह मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक बीते वर्षों के दौरान राज्य में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है. वर्ष 2017 में जहां बंगाल में 509 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हुई थीं, वहीं 2018 में यह आंकड़ा 1035 तक जा पहुंचा, जबिक वर्ष 2019 में जून तक 773 हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं.

पंचायत चुनाव में हिंसा

देशभर में कहीं भी चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग और राज्य सरकार की यह कोशिश रहती है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाएं, किन्तु देश का बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल आज राजनीतिक हिंसा के लिए कुख्यात हो चुका है. ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरह से हिंसा, अराजकता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन हो रहा है, वह लोकतंत्र के लिए घातक है. बंगाल में भाजपा के बढ़ते पंचायतों की 58,692 में से
20,076 सीटों पर एक भी वोट
पड़े बिना विजेता तय हो गया.
नामांकन के दौरान बड़े पैमाने पर
हिंसा हुई. भारतीय जनता पार्टी
के 20 से अधिक कार्यकर्ताओं
की हत्या कर दी गई और लगभग
1341 कार्यकर्ता जख्मी हुए.

जनसमर्थन से बौखलाई ममता तानाशाही के रास्ते पर हैं और अपने विरोधी विचारों के लोगों पर जुल्म करने से परहेज़ नहीं कर रही हैं. बंगाल के गत पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की कैसे धज्जियां ममता सरकार ने उड़ाई, यह पूरे देश ने देखा था. राजनीति में विरोध जायज है. राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप के जरिये विपक्षी दल को पराजित करने की रणनीति अपनाते हैं, जो लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुकूल भी है, लेकिन बंगाल में स्थिति भयावह है. सत्ताधारी दल तृणम्ल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सारी हदों को पार करते हुए भाजपा के एक दलित युवा कार्यकर्ता त्रिलोचन महतो की क्रूरता के साथ हत्या कर डाली थी. उसका कस्र यही था कि वह भाजपा का कार्यकर्ता था और तृणम्ल के विचारों का विरोधी था. ममता बनर्जी की इस अलोकतांत्रिक नीति के खिलाफ़ भाजपा ने बंगाल में लोकतंत्र को

बचाने का संदेश जन-जन तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क शुरू कर दिया है. गत पंचायत चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने हिंसा तथा अराजकता फैलाकर राज्य में भय का वातावरण बनाकर जनता को डराने का प्रयास किया था. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह एहसास हो चुका था कि बंगाल की जनता उनके कुशासन से त्रस्त आ चुकी है. पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़ती शक्ति से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ी हुई थी, जिससे बौखलाकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने हिंसा का सहारा लिया. सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखते हुए बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली कराई. स्थिति कितनी भयावह थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 34% सीटों पर बगैर चुनाव हुए परिणाम घोषित हो गए. इस दमन तथा हिंसा के बावजूद भाजपा ने पंचायत चुनाव में शानदार सफ़लता अर्जित करते हुए सात हजार से अधिक सीटों पर जीत हासिल की.

- पंचायतों की 58,692 में से 20,076 सीटों पर एक भी वोट पड़े बिना विजेता तय हो गया. नामांकन के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई.
- पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के

(Photo source- Indrajit Roy/IANS)



पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के खिलाफ आसनसोल में प्रदर्शन करते भाजपा कार्यकर्ता

20 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई और लगभग 1341 कार्यकर्ता जख्मी हुए.

- लगभग दो करोड़ मतदाताओं को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया.
- भाजपा ने इस पंचायत चुनाव में सात हजार से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त की.
- सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर उपद्रव फैलाए और विपक्षी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने से रोक दिया.
- राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 34 फ़ीसदी से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवारों को निर्विरोध चुने गए थे. आयोग के मुताबिक 48,650 ग्राम पंचायत सीटों में से 16,814 सीटें पर

- टीएमसी उम्मीदवारों को छोड़कर किसी दूसरे ने नामांकन नहीं किया. ये आंकड़ा 34.6 फीसदी है, जबिक पंचायत समिति की कुल 9,217 सीटों में से 3,509 यानी 33.2 फीसदी सीटों पर टीएमसी को छोड़कर किसी दूसरे ने पर्चा नहीं भरा.
- इसी तरह से जिला परिषद सदस्य की 825 सीटों में से 203 सीटों यानी 24.6 फीसदी सीटों पर टीएमसी उम्मीदवार को छोड़कर किसी दूसरे ने नामांकन नहीं किया. बीरभूम जिले में सर्वाधिक ऐसी सीटें थीं, जहां निर्विरोध रूप से उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की थी. बीरभूम में पंचायत की कुल 2,427 सीटों में से 1,967 सीटें निर्विरोध जीती गयी थीं.

तृणमूल कांग्रेस की मर्यादाहीन राजनीति

श्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर चुनावों के दौरान की गई आपत्तिजनक टिप्पणियाँ उनकी हताशा को दिखाती हैं. गौरतलब है कि भाजपा के पश्चिम बंगाल में बहते प्रभाव से ममता बनर्जी चिंतित हैं और इसी बौखलाहट में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भाषाई मर्यादा को ताक पर रख दिया है.राजनीति में शुचिता और भाषा की मर्यादा आवश्यक है, लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा तृणमूल के नेताओं ने राजनीतिक शुचिता की परवाह नहीं की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया.

 पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2019 के आम चुनावों में एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी को सत्ता और राजनीति से बाहर करना चाहिए और उनके मुंह को चिपकने वाले सर्जिकल टेप से बंद कर देना चाहिए.

- ममता ने अपने एक वक्तव्य में संवैधानिक पद की गरिमा की परवाह किए बगैर कहा कि पीएम मोदी को थप्पड़ मारने का मन करता है. मैंने ऐसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं देखा, जब चुनाव आते हैं तो राम नाम जपने लगते हैं
- जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे. ममता ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना को खारिज करते हुए उन्हें 'गधा' तक कह दिया.
- टीएमसी नेता और लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. एक रैली

को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कोलकाता से ऐसा आंदोलन उठेगा कि मोदी 'चूहे के बच्चे' की तरह गुजरात भाग जाएंगे. इसके अलावा कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक वाहियात प्रधानमंत्री बताया था.

- रानीगंज में एक रैली को संबोधित करते ह़ए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी को कंकड़ भरे लड्डू देने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि ''नरेंद्र मोदी वोट मांगने बंगाल आ रहे हैं. लेकिन उन्हें कंकड़ भरे और मिट्टी से बने लड्डू ही मिलेंगे, जिसे चखने के बाद उनके दांत टूट जाएंगे." ज्ञातव्य हो कि ममता बनर्जी की यह टिप्पणी उस सन्दर्भ में है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को एक गैर राजनीतिक साक्षात्कार में कहा था कि 'ममता दीदी उन्हें हर वर्ष कुर्ते और मिठाइयाँ भेजती हैं'. यह ध्यान आता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री अब इस स्थिति में हैं कि वह सकारात्मक चीजों को भी राजनीति से जोड देती हैं.
- तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने भाजपा अध्यक्ष

अमित शाह पर उनकी 'कंगाल बांग्ला' टिप्पणी को लेकर उन्हें एक 'घटिया' एवं 'कुख्यात' व्यक्ति बताया था. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने राज्य में विकास को बाधित करने का काम किया और इसी सन्दर्भ में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि भाजपा बंगाल की पारंपरिक छिव को लौटाएगी और उसे सोनार बांग्ला बनाएगी.

- चुनाव परिणाम के बाद प्रेस कांफ्रेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हुआ कहा कि 'लोकतंत्र में धनबल काम कर रहा है. ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे राज्यों में विपक्ष के पास कोई सीट न हो!
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 'मैं इस बार भी इफ्तार में जाऊंगी. मैं तो मुस्लिम तृष्टिकरण करती हूं, जरूर करूंगी, जो गाय दूध देती है उसकी लात खानी चाहिए'. इस प्रेस कांफ्रेंस ने ममता बनर्जी की बौखलाहट और उनकी कार्यशैली को सभी के समक्ष उजागर करने का काम किया है.

तुष्टिकरण की राजनीति

हिन्दुओं को वोट डालने से रोका गया

- गत लोकसभा चुनाव में रायगंज लोकसभा क्षेत्र में हिन्दू वोटरों को वोट देने से रोक दिया गया था. इससे पहले हिन्दुओं को डराने का प्रयास भी जगह-जगह किया गया. एक न्यूज़ चैनल ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट किया था. रिपोर्ट में यह देखा गया कि कैसे किसी हिन्दु के नाम पर कोई और मतदान कर रहा था.
- सातगछिया विधानसभा में हिन्दुओं को मतदान करने से पहले ही भगा दिया गया.
 वहाँ के सभी घरों को जबरन खाली करा दिया गया था. इस मामले में टीएमसी नेता सौकत मुल्ला का नाम सामने आया था.
- ममता बनर्जी ने शाहजहाँ शेख नाम के एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता बताया, किन्तु इसकी पड़ताल की गई तो यह पता चला कि शाहजहाँ शेख अपने इलाके में कटमनी का सबसे बड़ा डीलर है. वह सोना तस्करी, महिला तस्करी जैसेअसंवैधानिक कार्यों को अंजाम देता है. शाहजहाँ शेख पर

दंगा फैलाने, मर्डर करने का भी आरोप है. संदेशखाली में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं सुकंतों मंडल,प्रदीप मंडल और शंकर मंडल की गोली मार हत्या कर दी गई थी, जिसमें शाहजहाँ शेख मुख्य आरोपी है.

दुर्गा पूजा पर रोक

ममता सरकार ने 2017 में पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दिया था. दुर्गा पूजा के अगले दिन मोहर्रम होने के कारण मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था. ममता ने कहा था कि मोहर्रम होने के कारण दुर्गापूजा के बाद मूर्ति विसर्जन की इजाजत नहीं दी जा सकती. राज्य सरकार ने दशमी और उसके एक दिन बाद तक मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी. ममता ने कहा था कि या तो विसर्जन दशमी के दिन 6 बजे से पहले हो जाए या दो दिन के बाद. इससे पहले 2016 में कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता ने राज्य सरकार को इस मसले पर फटकार लगाई थी, किन्तु ममता ने उसे नजरअंदाज कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा था कि ममता सरकार का यह बहुत ही खतरनाक

कदम है, जिसमें वो धर्म को राजनीति में शामिल कर रही हैं. इसका परिणाम यह होगा कि दोनों समुदायों में खाई और बढ़ जाएगी, कोर्ट के अनुसार –"There has been a clear endeavour on the part of the state government to pamper and appease the minority section of the public at the cost of the majority section without there being any plausible justification. The reason therefore is, however, not far to seek.The administration has failed to take note of the fact that Muharram is also not the most important festival of people having faith in Islam... To put it curtly, the state government has been irresponsibly brazen in its conduct of being partial to one community, thereby infringing upon the fundamental rights of people worshipping Maa Durga,"

सरस्वती पूजा

पश्चिम बंगाल में सरस्वती पूजा करने को लेकर भी विवाद हुआ था. प्रदेश में कई विद्यालयों में सरस्वती पूजा सिर्फ इसलिए नहीं मनाई गई, क्योंकि मुस्लिम समाज का विरोध झेलने के लिए कोई तैयार नही था. मुस्लिम समुदाय के कई लोग यह मांग कर रहे थे कि पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन को भी सभी विद्यालयों को मनाना चाहिए. राजरहाट इमाम काउंसिल ने यह मांग रखी थी. हावड़ा के तेहत्ता में विद्यालयों को ही बंद करना पड़ा था, क्योंकि विद्यालय में नबी दिवस नहीं मनाया गया था. ऐसे ही हुगली के जंगीपाड़ा में सरस्वती पूजा कई सालों से नहीं मनाने दिया जाता है.यह सब घटनाएँ पूरे बंगाल में घटित हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इसपर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है.

रामनवमी

श्रीराम भारतीय समाज में आस्था के केंद्रबिंदु हैं. हर साल राम नवमी को देश भर में राम शोभा यात्रा और रैलियों का आयोजन हर्षोल्लास के साथ होता है, किन्तु बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राम रथ यात्रा या रामनवमी का जूलूस चुभता है. वह कई बार रामनवमी शोभायात्रा की खुलकर आलोचना भी कर चुकी हैं. दरअसल, इस आलोचना से उनकी तुष्टिकरण की राजनीति को फायदा

2013 में पहली बार बंगाल के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने अलग 'मुगलिस्तान' की मांग शुरू कर दी. इसी साल बंगाल में हुए दंगों में सैकड़ों हिंदुओं के घर और दुकानें लूटे गए, साथ ही कई मंदिरों को तोड़ दिया गया. इन दंगों में पुलिस ने लोगों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की.

होता है. हर वर्ष रामनवमी को राज्य में हिंसा होती है और रामनवमी की यात्रा की अनुमति भी ममता सरकार नहीं देती. हिन्दुओं के इस पर्व में भी तृणमूल सरकार अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराती आई है.

इस वर्ष 13 और 14 अप्रैल को राम नवमी की रैलियों का आयोजन होने वाला था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने विश्व हिन्दू परिषद को रैली निकालने की इजाजत नहीं दी. विश्व हिन्दू परिषद की बाइक रैली शुरू ही नहीं हुई थी, उससे पहले ही पुलिस ने रैली पर रोक लगा दी.

- प्रत्येक वर्ष राम नवमी में राम भक्त शोभा यात्रा निकालते हैं, किन्तु प्रशासन उनके समुचित सुरक्षा का इंतजाम नहीं करती है.
- पिछले वर्ष राम नवमी के मौके पर भारी हिंसा हुई थी, आसनसोल में तो हिन्दू

- पलायन करने को मज़ब्र हो गए थे.
- गत वर्ष पुरूलिया, मुर्शीदाबाद, बर्धमान वेस्ट और रानीगंज सिंहत विभिन्न स्थानों पर रामनवमी के जुलूस के दौरान हिंसक घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई थी और करीब 10 से अधिक लोग घायल हुए थे.
- राम शोभा यात्रा में शामिल लोगों को सुरक्षा मुहैया ना करा पाने वाली मुख्यमंत्री राम भक्तों को 'गुंडा' कहकर संबोधित किया था.

इमामों का बढ़ाया भत्ता

बंगाल में लगभग 27 फीसद मुस्लिम आबादी है, ममता बनर्जी ने इस वर्ग को लुभाने के लिए सारी मर्यादाओं को लांघ दिया है. कट्टरपंथी समूहों को प्रसन्न करने के लिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पहले कार्यकाल में इमामों के लिए भत्ता देने की घोषणा की थीं. अप्रैल 2012 में ममता बनर्जी ने इमामों के लिए 2500 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की थीं और मुअज्जिन के लिए 1500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की थीं. पश्चिम बंगाल राज्य भाजपा इकाई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस फैसले को 2013 में चुनौती

दी थी. उच्च न्यायालय ने इस भत्ता योजना को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन था. ममता बनर्जी ने समुदाय विशेष को खुश करने के लिए अप्रत्यक्ष मार्ग को चुना और राज्य के वक्फ बोर्ड के माध्यम से भत्ते का भुगतान करने की व्यवस्था की गई. राज्य सरकार ने हिंदू पुजारियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और राज्य में इमामों और मौलवियों को खास तरजीह दी.

कानून-व्यवस्था से खेलता एक 'विशेष समुदाय'

बंगाल में एक विशेष समुदाय को कानून व्यवस्था का कोई भय नहीं रह गया है. 2013 में पहली बार बंगाल के कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं ने अलग 'मुगलिस्तान' की मांग शुरू कर दी. इसी साल बंगाल में हुए दंगों में सैकड़ों हिंदुओं के घर और दुकानें लूटे गए. साथ ही कई मंदिरों को तोड़ दिया गया. इन दंगों में पुलिस ने लोगों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की. मुस्लिम तुष्टिकरण का नतीजा है कि शाही इमाम सैयद मोहम्मद नूर्रिहमान बरकती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित 'फ़तवा' जारी किया था. बंगाल में मुस्लिम युवा बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं और पुलिस मूकदर्शक की भूमिका में नजर आती है.

आतंरिक सुरक्षा में फेल ममता सरकार

- पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के
 मल्लारपुर में 29 जून की रात एक स्थानीय
 क्लब में भारी विस्फोट हुआ. इस घटना
 में क्लब के तीन लोहे के गेट पूरी तरह
 क्षतिग्रस्त हो गए. इसके अलावा आसपास
 के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा था.
 क्लब में विस्फोट कैसे हुआ? यहां पर
 इतनी भारी मात्रा में विस्फोट किसने रखा
 था? इसपर पुलिस ने जांच की बात कहकर
 चुप्पी साध ली.
 - 12 मई 2015 को कोलकाता में एक लोकल ट्रेन में हुए धमाके में 25 लोग जख्मी हो गए थे. घायलों में 5 की हालत गंभीर थी. यह ट्रेन सियालदह से कृष्णानगर जा रही थी, जिस वक्त ट्रेन बैरकपुर और टीटागढ़ रेलवे स्टेशन के बीच थी, तभी इसमें धमाका हो गया. शुरुआती जांच में साफ हुआ था कि धमाके से ठीक पहले यात्रियों की कुछ संदिग्धों के साथ कहासुनी हुई थी.

पश्चिम बंगाल सरकार के
2019-20 के बजट के अनुसार
तृणमूल काँग्रेस की सरकार ने
अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों
के विकास के लिए राज्य में उच्च
शिक्षा से ज्यादा धन आवंटन
किया है.

• 02 अक्तूबर 2014 को बर्धमान के एक घर में बम ब्लास्ट हुआ था. इस हादसे को अंजाम देने में आतंकी संगठन जमात-उल-मुजाहिदीन बांग्लादेश के स्लीपर सेल का हाथ था. जब आतंकी बम प्लांट कर रहे थे, तभी दो आतंकियों की बम फटने की वजह से मौत हो गई थी और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया था. ध्यान देने वाली बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर भी उसी मकान के निचले हिस्से में था, जहाँ ब्लास्ट हुआ था.

ममता सरकार का तुष्टिकरण वाला बजट

 भारत में पुनर्जागरण का सूत्रपात करने वाला बंगाल आज ममता बनर्जी का तृष्टिकरण वाला बंगाल है. वह मुस्लिम तृष्टिकरण की राजनीति में इतना आगे

- बढ़ गई हैं कि उन्हें अपने वोटों के आगे आधुनिक शिक्षा को भी प्रभावित करने से गुरेज नहीं है.
- पश्चिम बंगाल सरकार के 2019-20 के बजट के अनुसार तृणमूल काँग्रेस की सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के विकास के लिए राज्य में उच्च शिक्षा से ज्यादा धन आवंटन किया है.
 - ममता सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए जहां 3,964 करोड़ का बजट दिया है. वहीं मदरसों के विकास के लिए 4,016 करोड़ का बजट आवंटन किया है. बजट में आधारभूत ढांचे के लिए यानी पीडब्लुडी के लिए मात्र 5,336 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है.
- 2018-19 के बजट में ममता सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 3,713 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया था.
 पिछले साल मदरसों के विकास और अल्पसंख्यक मामलों के लिए 3,258 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबिक इस साल बजट में मदरसों के लिए 4,016 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिसमे 23% की वृद्धि की गई है.
- इसी तरह ममता बनर्जी की सरकार ने

2017-18 के बजट में भी बड़े उद्योगों, लघु और मध्यम उद्यमों, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर अपने संयुक्त व्यय की तुलना में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसों के लिए अधिक धन आवंटित किया था

- तृणमूल सरकार ने अल्पसंख्यक और मदरसों के लिए 2,815 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जबिक वित्त वर्ष 2017-18 में उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के लिए सिर्फ 2,154 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई.
- पिछड़े वर्गों के विकास, आदिवासी कल्याण के लिए 2,775 करोड़ रुपये का आवंटन और सिंचाई और जलमार्ग के लिए 2,410 करोड़ रुपये का आवंटन भी तृणमूल सरकार के अल्पसंख्यक बजट से काफी कम है.

पश्चिम बंगाल में तृणमूल काँग्रेस की सरकार निरंतर पश्चिम बंगाल की मुख्य समस्याओं को दरिकनार करती आई है. वोटबैंक की राजनीति को प्रमुखता देते हुए पूरे राज्य में मुस्लिम तृष्टिकरण का वातावरण बना रखा है. ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य के बजट में मुस्लिम वोटबैंक को ध्यान में रखते हुए मदरसों के लिए आवंटन में लगातार वृद्धि की है. गौरतलब है कि ममता सरकार ने मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, जल, सिंचाई और आधारभूत संरचना समेत सूचना प्रौद्योगिकी पर्यटन आदि सभी क्षेत्रों में धन की कटौती कर बंगालवासियों को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम किया है. अगर तृणमूल सरकार के कामकाजों का निष्कर्ष निकालें तो, 2011 के विधानसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने वामदलों का साथ छोड़कर तृणमूल काँग्रेस का समर्थन किया था. इसी की भरपाई करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उन 27 प्रतिशत मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए पश्चिम बंगाल के समग्र विकास को दरिकनार कर रही हैं. जातव्य हो कि ममता सरकार ने गरीबों, आदिवासियों, वंचितों के साथ अन्याय करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने वोटबैंक को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है. तृणमूल सरकार का हर वर्ष बंगाल के लिए आवंटित होने वाला बजट सिर्फ एक समुदाय को समर्पित रहता है. फिर चाहे इसके लिए बच्चों की उच्च शिक्षा, गरीबों का कल्याण या युवाओं के सपनों को ही क्यों न कुचलना पडे ?

संघीय ढांचे को तहस-नहस करने में जुटी हुई हैं ममता बनर्जी

- एनआरसी का मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है,केंद्र सरकार इसे पूरे देश में लागू करना चाहती है, इसपर ममता केंद्र सरकार पर विफरी हुई हैं, उनका गुस्सा इतना बढ़ गया कि इस मामले को लेकर कई आपत्तिजनक बयान दिए. ममता ने कहा कि एनआरसी के प्रावधानों को लागू करने की स्थिति में देश में ख़ून-ख़राबे की नौबत आ जाएगी और गृहयुद्ध छिड़ जाएगा.
- ममता ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए इस कवायद को गलत करार दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने बेसिर पैर का बयान देते हुए यहां तक कह डाला था कि यदि सरकार ने यह काम नहीं रोका तो देश में गृहयुद्ध भी छिड़ सकता है. बांग्लादेशी घुसपैठियों का इस तरह हितैषी बनकर सामने आना, ममता को भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन गृहयुद्ध की उनकी भाषा किसी को रास नहीं आई. गौरतलब है कि 2005 में उन्होंने संसद में घुसपैठ को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना था.

- इतना ही नहीं, ममता को जब बोलने नहीं दिया गया, तो उन्होंने बड़ा हंगामा करते हुए कागज फाड़कर फेंक दिए थे.
- शारदा चिटफंड घोटाला मामले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ करने के लिए सीबीआई का उनके पास पहुंचना, ममता बनर्जी की सरकार को इतना अखरा कि उनकी पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को ही हिरासत में ले लिया ये संघीय ढाँचे के प्रतिकुल कार्यवाही थी. ऊपर से ममता बनर्जी लोकतंत्र बचाने के कथित अभियान के साथ अनशन पर बैठ गईं. मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और न्यायालय ने सभी पहलुओं को देखने के बाद यह निर्णय सुनाया कि अब सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ करने नहीं जाएगी, बल्कि वे सीबीआई के सामने पेश होकर उसके सवालों का जवाब देंगे
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया
 कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित
 डोभाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा

अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से सीबीआई को निर्देश दिए जा रहे हैं.

- दिसंबर 2016 में सेना के एक रूटीन अभ्यास पर उन्होंने कह दिया था कि केंद्र सरकार सेना भेजकर उनकी सरकार गिराना चाहती है.
- नीति आयोग की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ने शामिल होने से इनकार कर दिया. यह जानना आवश्यक है कि राज्य एवं केंद्र एक-दूसरे के साथ मिलकर देश को प्रगति के पथ पर ले जाएँ, इस नजरिए से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है.
- भमता बनर्जी ने नीति आयोग को अपमानित करते हुए एक पत्र में लिखा कि जब नीति आयोग के पास कोई अधिकार ही नहीं है, तो बिना मतलब की इस बैठक में आने का क्या फायदा? उन्होंने कहा कि नीति आयोग के पास न तो कोई वित्तीय शक्तियां हैं और न ही राज्य की योजनाओं में मदद के लिए उसके पास शक्ति है. ऐसे में किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्तियों से वंचित ऐसी संस्था की बैठक में शामिल होना, उनके लिए निरर्थक है.
- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में शामिल

- होने से इनकार करके यह साबित कर दिया है कि वह अभी भी चुनाव के दौर वाली मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाई हैं. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हितों की अनदेखी की है.
- ज्ञातव्य हो कि यह वही ममता बनर्जी हैं जो एक समय अपने नेतृत्व वाले राजनीतिक मोर्चे का नाम संघीय मोर्चा रख रही थीं, जिससे राज्यों के अधिकारों को प्राथमिकता देती हुई दिखाई पड़ सकें, मगर आज उन्हें संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ खड़े होने में कोई गुरेज नहीं है. लोकसभा चुनाव में जनता द्वारा दिए गए जनादेश को स्वीकार करने में भी ममता बनर्जी को मुश्किल हो रही है. यहां तक कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथग्रहण में आमंत्रण के बावजूद आने से इनकार कर दिया.
- भयंकर फानी तूफ़ान के समय जब बंगाल संकट में था, तो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठाया.
- वर्तमान में ममता बनर्जी को संविधान से कोई सरोकार दिखता नहीं है. ऐसा प्रतीत

होता है, जैसे वे बंगाल में एक अलग ही ढंग से शासन चलाने में जुटी हुई हैं. हाल के उनके कुछ निर्णयों एवं वक्तव्यों पर नजर डालें तो स्थिति स्पष्ट होती नजर आती है. चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि वे नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री ही नहीं मानती हैं. देश के मतदाताओं के द्वारा बहुमत से चुने गए प्रधानमंत्री के प्रति एक राज्य की मुख्यमंत्री का इस तरह की बात कहना, क्या देश की जनता और लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान नहीं है?

- केंद्र सरकार जब भी कोई जानकारी राज्य सरकार से मांगती है तो ममता भड़क उठती हैं.
- राज्यपाल जब भी ममता से मिलना चाहते हैं अथवा फोन पर बात करना चाहते हैं,
 ममता बनर्जी कोई जवाब नहीं देती हैं.
- केंद्र सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि को राज्य में लागू नहीं किया है.

ममता बनर्जी ने किया भारतीय सेना का अपमान

 चुनाव के समय शांतिपूर्ण मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सुरक्षा की टीमें गईं

- थीं और ममता ने उन्हें बार-बार बीजेपी का एजेंट बताया था.
- भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में जब एयर स्ट्राइक हुई, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया और कहा कि इस कार्रवाई में कितने आतंकी मारे गए, इसका कोई प्रमाण है तो सामने आना चाहिए.
- जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी,
 2019 को जैश के आत्मघाती आतंकियों
 ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना
 बनाया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए
 थे. इसके बाद मसूद अजहर के आतंकी
 संगठन की इस करतूत का जवाब देते हुए
 26 फरवरी,2019 को देर रात भारतीय
 वायुसेना ने पाकिस्तानी की सीमा में घुसकर
 जैश के आतंकी कैंपों पर एयरस्ट्राइक की
 थी
- एयरस्ट्राइक को लेकर तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि 'मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि इस ऑपरेशन में कोई नहीं मारा गया और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में एक मौत की बात कही गई है. इसलिए हम इसकी पूरी

जानकारी चाहते हैं.' साथ ही उन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव से पहले जवानों के खून पर राजनीति करने का आरोप लगाया. ममता ने कहा कि वायु सेना के इस हमले में कितने लोग मारे गए और मरने वालों में कौन लोग थे? सरकार को इसका विस्तृत विवरण जारी करना चाहिए.

- जब हमला आतंकी कैम्प पर हुआ है, जिसे पाकिस्तान ने भी स्वीकार किया, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष होने के नाते हम ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी चाहते हैं. सरकार बताए कि कहां बम गिराए गए, कितने लोग उसमें मारे गए?
- एयरस्ट्राइक पर तीनों सेना के प्रमुखों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि हमारे पास एयरस्ट्राइक के सबूत हैं और अगर जरुरत पड़ी तो हम इसे सार्वजनिक करेंगे. इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक पर भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सबूत मांगे थे. इतना ही नहीं ममता बनर्जी ने एयरस्ट्राइक के बाद यह भी कहा कि 'कुछ विरष्ठ पत्रकारों ने मुझे बताया है कि एक और हमला (स्ट्राइक) होगा. मैं नहीं कह सकती कि किस तरह का हमला होगा. अजीबोगरीब स्थिति है कि जब पूरा देश सेना और सरकार का समर्थन

कर रहा था. ऐसे में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ नेताओं ने सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े करने का फैशन बना लिया है.

चुनाव आयोग पर ममता का हमला

- पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव के दौरान बार-बार स्वायत्त संस्थाओं को बदनाम कर रही थीं, उनकी स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता पर लगातार चोट कर रही थीं. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनाव प्रक्रिया को सफल ढंग से पूरा करने के लिए समूचे विश्व द्वारा चुनाव आयोग का अभिनन्दन हो रहा है, वहीं टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग को निकम्मा और निराशा आयोग बताया है.
 - ममता बार-बार लोकतंत्र बचाओ के नारे दे रही थीं, किन्तु खुद लोकतंत्र का अपमान करती रही हैं. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनावों में आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा है. गौरतलब है कि 2019 के आमचुनावों में पश्चिम बंगाल के अन्दर

राजनीतिक हिंसा को देखते हुए चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के गृह सचिव अत्रि भट्टाचार्य व एडीजी (सीआइडी) राजीव कुमार पर एक्शन लिया और अंतिम चरण के चुनावों में प्रचार अभियान पर समय से पहले रोक लगाने का आदेश दिया था. इसपर ममता बनर्जी बिफर पडीं और कह दिया कि 'कानून-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है, चुनाव आयोग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित किया जा रहा है. मोदी-शाह के निर्देश पर चुनाव आयोग कार्य कर रहा है, आयोग का यह फैसला असंवैधानिक, अनैतिक व राजनीति से प्रेरित है. मैंने ऐसा चुनाव आयोग पहले न कभी देखा और न ही सुना है. यह फैसला चुनाव आयोग का नहीं बल्कि मोदी-शाह का फैसला है."

 चुनाव आयोग के द्वारा जल्द प्रचार रोकने के फैसले पर उन्होंने कहा कि अमित शाह दंगा कराने के मूड में बंगाल आये थे और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था. इसके अलावा ममता बनर्जी ने अमित शाह पर चुनाव आयोग को धमकी देने का भी आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी अपने बाहुबल से सभी संस्थानों को हाईजैक कर रहे हैं.

- चुनाव के दौरान ममता बनर्जी को बार-बार चुनाव आयोग के खिलाफ जनता को भड़काते हुए देखा गया.
- वह चुनाव आयोग पर पूरी तरफ खफा थीं और आयोग के हर फैसले पर अपना विरोध दर्ज करा रही थीं. मसलन पहले चुनाव प्रचार रोकने का मामला हो, निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए केन्द्रीय सुरक्षा बलों को भेजने की बात हो, वह चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगा रही थीं.
- उन्होंने लगातार चुनाव आयोग को बदनाम करने तथा आयोग की विश्वनीयता को भंग करने का प्रयास किया.
- लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद भी ममता बनर्जी अपना ईवीएम प्रलाप जारी रखा, पिछले दिनों प्रेस कांफ्रेंस करके उन्होंने कहा कि विपक्षी दल मतपत्रों के जिए चुनाव करवाने की मांग एक साथ मिलकर करें.
- बंगाल की मुख्यमंत्री ने इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले जनसमर्थन का अपमान करते हुए कहा कि वह इस जनादेश को स्वीकार नहीं करतीं हैं.

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संकट

- पश्चिम बंगाल निवेश की दृष्टि से प्रतिकूल राज्य रहा है. प्रमुख एंबेसडर कार की कंपनी 2014 में बंद हो गई थी. बंगाल वही राज्य है, जिसने 2008 में सिंगूर में टाटा समूह के नैनो कारखाने को लगाने से इनकार कर दिया था. सिंगूर विरोध की सूत्रधार ममता बनर्जी 8 साल से अधिक समय से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं.
- वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल में कोलकाता के बाहर केंद्र विकसित करने के लिए 50 एकड़ जमीन खरीदने में 75 करोड़ रूपये का निवेश कर चुकी इन्फोसिस को 2011 में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारी बहुमत

- से आई ममता सरकार ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था.
- जिंदल समूह के मामले में तृणमूल सरकार ने धमकी दी कि वाम मोर्चा सरकार के दौरान उद्योग लगाने के लिए अधिग्रहीत जमीन पर, वह निवेश करें या फिर सिंगूर जैसे हालात का सामना करें.
- बीते दस वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र में किसी बड़े निवेश के ना होने से राज्य के औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर घट गए हैं, जिसके कारण युवाओं को अन्य जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है.

पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं की स्थिति

केंद्रीय योजनाओं की उपेक्षा

ममता बनर्जी ने बंगाल में तमाम केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं किया है. केंद्र सरकार की गरीबों को पांच लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान योजना वहां लागू नहीं की गई है, इस योजना के तहत 60 प्रतिशत खर्च केंद्र को और 40 प्रतिशत राज्य सरकार को वहन करने का प्रावधान है. इसी बात को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने अपने हिस्से का खर्च वहन करने से इनकार करते हुए, इस योजना से बाहर रहने का एलान कर दिया. स्वास्थ्य, राज्य सूची का मामला है, लिहाजा इसमें राज्य सरकार की सहमति के बिना केंद्र सरकार बहुत कुछ कर नहीं सकती. ममता का ऐसा ही गतिरोधी रुख 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' को लेकर भी है, जिसका पुरा खर्च केंद्र वहन कर रहा है, किसान सम्मान निधि योजना में राज्यों की भूमिका बस इतनी है कि उन्हें अपने यहां से इस राशि की पात्रता रखने वाले किसानों की सूची भेजनी है, लेकिन केंद्र द्वारा बार-बार कहे जाने के बावजूद अब तक पश्चिम बंगाल से सूची नहीं भेजी गई है, जिस कारण वहां के किसान इस योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं. गौरतलब है कि संविधान में केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर तमाम प्रावधान करते हुए यही अपेक्षा की गई है कि ये दोनों परस्पर समन्वय और समझ के साथ राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करेंगे, मगर पश्चिम बंगाल सरकार का जो रवैया है, वह इस संवैधानिक अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत है.

केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का नाम परिवर्तन:

- 'आजीविका योजना' का नाम परिवर्तित करके आनंदधारा कर दिया है.
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का नाम बदलकर बांगलार ग्रामीण सड़क योजना.

- 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का नाम बदलकर 'बांगलार गृह प्रकल्प' कर दिया.
- 'स्वच्छ भारत मिशन' का नाम बदलकर
 'मिशन निर्मल बांगलार' कर दिया है.

पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभ

- स्वच्छ भारत अभियान को पश्चिम बंगाल की सरकार ने निर्मल बांग्ला अभियान के साथ ही लागू किया है, जिसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में जुलाई तक 61,58,112 लाख शौचालय बनाये जा चुके हैं. 2015 से पहले बंगाल में कोई भी जिला खुले में शौच से मुक्त नहीं था, लेकिन अब 19 जिले खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं. गंगा नदी के किनारे पश्चिम बंगाल के 2158 गाँवों को नमामि गंगे अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है. अगस्त 2019 तक बंगाल के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा.
- 30 जनवरी 2019 तक स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत 180.16

- करोड़ रुपये की लागत से पश्चिम बंगाल में 24 घाटों और श्मशान की परियोजनाओं को पुरा किया गया है. ये श्मशान और घाट कोलकाता, बाँसबेरिया, हावड़ा, सीरामपुर, खारदाह, नैहाटी, चंदननगर, बैद्यबती, पनिहाटी, कमरहटी, बल्ली, टीटागढ़, महेस्ताला, उत्तरी बैरकप्र, हुगली-चिनसुरा, कुँगर, हलिशहर, बुडगे, बुडापारा में बनाई गई है. इसके अलावा एंट्री लेवल एक्टिविटीज के तहत घाटों और क्रेमेटोरिया की 7 और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 48.47 करोड़ रुपये की लागत से 15 घाटों और 4 इलेक्ट्रिक श्मशान का जीर्णोद्धार और विकास शामिल है.
- केंद्र सरकार ने देशभर में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए एवं निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) को एक सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) इकाई के रूप में स्थापित किया है. पश्चिम बंगाल में कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुल 10,711 महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 4,196 को

प्लेसमेंट मिला है.

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 6 जुलाई 2019 तक नामांकित अभ्यर्थियों की संख्या 63,378 है, जिसमे से 975 अभ्यर्थियों ऐसे हैं, जिनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है. अभी तक 43,597 अभ्यर्थियों की प्लेसमेंट हो गया है और कुल 62,403 अभ्यर्थियों का ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है.
- उज्ज्वला योजना के तहत बंगाल में 4 जुलाई 2019 तक कुल 81,24,194 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया जा चुका है, जो अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी अधिक है.
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत 7.32 लाख घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है, जिससे 100% विद्युतीकरण पश्चिम बंगाल में हो चुका है.
- उजाला स्कीम के अंतर्गत 6 जुलाई
 2019 तक 92,28,789 एलइडी बल्ब बांटे जा चुके हैं.
- सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत बंगाल में
 अबतक बंदरगाहों के विकास के लिए
 14,268 करोड़ रूपए का निवेश किया

जा चुका है. खिदिरपुर और दक्षिण 24 परगना, सोनापुर में 2 सूखे बंदरगाहों का विकास प्रगति पर है. सुंदरबन और स्वरूपनगर नदी पर 206 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जलमार्ग का कार्य समाप्त हो चुका है. अजोय और इछामती नदियों में राष्ट्रीय जलमार्ग का विकासकार्य प्रगति पर है. इसके अतिरिक्त ताजपुर में भी एक नए बंदरगाह का विकास किया जा रहा है.

- पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ से ओडिशा के भद्रक तक तीसरी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसकी लागत 1,866 करोड़ रूपए है. इस लाइन का काम 2023-24 तक ख़त्म होने की सम्भावना है.
- नेशनल हाइवे ब्रिज— NH-31A के फालाकाटा-सल्सलाबरी सेक्शन में एक नया फोर लेन हाईवे 1,938 करोड़ रूपए की लागत से बनाया जा रहा है.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत
 31 मार्च 2018 तक पश्चिम बंगाल के
 55.91 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके
 हैं.
- प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत
 30 जनवरी 2019 तक कुल 3.4 करोड़

- खाते खोले जा चुके हैं और 2.8 करोड़ RuPay Cards जारी किये जा चुके हैं.
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 31
 जनवरी 2019 तक 7 लाख लाभार्थियों
 को इसका लाभ मिल रहा है, जिसमें
 46% महिलाएं हैं.
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के
 द्वारा 26 जून 2019 तक 12.51 लाख
 लाभार्थियों की उपस्थिति पंजीकृत है.
- नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत 30 जनवरी 2019 तक पश्चिम बंगाल के 19 में से 18 जिले को कवर किया जा चुका है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत
 30 जनवरी 2019 तक 1,02,895 घर लाभर्थियों को मिल चुके हैं.
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 30 जनवरी 2019 तक 10.21 लाख हेक्टेयर खरीफ भूमि एवं 10.01 लाख हेक्टेयर रबी फसल भूमि का बीमा किया जा चुका है.
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 30 जनवरी 2019 तक 15,365.44 हेक्टर भूमि को कवर किया जा चुका है.

- 30 जनवरी 2019 तक पश्चिम बंगाल के किसानों को लगभग 64 लाख सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किये जा चुके हैं.
- पोषण अभियान के तहत 30 जनवरी 2019 तक 61 हज़ार 896 आंगनबाड़ियाँ कवर की जा चुकी हैं. लगभग 5.4 लाख बच्चे और 1.14 लाख गर्भवती महिलाएं मिशन इन्द्रधनुष के अंतर्गत लाभान्वित हो चुकी हैं.
- 31 मार्च 2019 तक पश्चिम बंगाल में कुल 1063 स्टार्ट-अप्स को मान्यता प्राप्त हो चुकी है.
 - नेशनल स्कॉलरशिप मिशन के अंतर्गत अकादिमक वर्ष 2018-19 तक 34.27 लाख एप्लीकेशन प्रमाणित किया गए हैं.
 - 30 जनवरी 2019 तक पश्चिम बंगाल की
 2,123 ग्राम पंचायतों को भारतनेट की
 ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध हो चुकी है.
- 30 जनवरी 2019 तक 100 अटल टिंकरिंग लैब्स अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत चल रही है.
- लगभग 1.5 करोड़ रूपए पश्चिम बंगाल को 30 जनवरी 2019 तक मुद्रा लोन के रूप में आवंटित किया गया है.

परिवर्तन की राह पर पश्चिम बंगाल

श की राजनीति में 2019 का लोकसभा चुनाव इस नाते भी अलग रहा क्योंकि इसबार चुनाव की धुरी पश्चिम बंगाल बना हुआ था. भाजपा के लिहाज से बंगाल की भूमि इससे पहले कभी इतनी उर्वरक नहीं रही. यह इतिहास में पहली बार हुआ जब बंगाल की 18 लोकसभा सीटों पर भाजपा को विजय मिली और 40 फीसद से अधिक मतदाताओं के मानस में भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति भरोसा मुखर होकर नजर आया. इतिहास में पहली बार था कि पूरब की धरा चुनाव की धुरी बन रही थी. यह इतिहास का वह पड़ाव है, जिसे प्रब की राजनीति में लंबे समय तक नहीं भूलाया जा सकेगा, इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अपार लोकप्रियता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कुशल रणनीति और अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवटता के साथ जुटे रहने वाले पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम और बलिदान है. हिंसा के वातावरण और तृणम्ल सरकार द्वारा पैदा की जा रही कठिनाइयों के बीच

बंगाल की चुनावी जंग एक कठिन युद्ध की तरह थी, जिसे लड़ने के लिए जमीन पर जूझने वाले कार्यकर्ताओं को साहस के साथ लड़ना था. भाजपा नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं के मन में साहस का भाव जागृत करने में रणनीतिक स्तर पर सफलता हासिल की. हिंसा के दौर और भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले और उनकी की जा रही हत्याएं भी कमल को खिलने से नहीं रोक सकीं. कार्यकर्ताओं का अपने दल और अपनी विचारधारा के लिए दिया गया बलिदान व्यर्थ नहीं गया.

यह चुनाव क्षेत्रीयता की संकुचित सोच से प्रदेश को निकालकर स्थानीय प्रतीकों, महापुरुषों तथा बंगाल की धरा से निकलकर देश-विदेश तक ख्याति अर्जित करने वाले महान विभूतियों को राष्ट्रीय फलक पर प्रस्तुत करने वाला था. बंगाल के इतिहास एवं उसके वर्तमान का राष्ट्रीय महत्व देश ने देखा भी और महसूस भी किया.

राष्ट्रवाद की विचारधारा को देश की राजनीति का अधिष्ठान बिंदु बनाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल

का बंगाल की भूमि पर अपनी विचारधारा को आम जनमानस के हृदय तक पहुंचा पाना एक बड़ी सफलता है. इस सफलता का असर दूरगामी और बहुकोणीय सिद्ध होगा. बंगाल की राजनीति में भाई-भतीजावाद, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार और लोकतंत्र के दमन की राजनीति करने वालों के लिए यह चुनाव एक चोट देने वाला सबक है. यह हिंसा की राजनीति पर लोकतंत्र की विजय है. यह क्षेत्रवाद की संकुचित सोच पर बंगाल के व्यापक राष्ट्रीय महत्व की विजय है.

बंगाल के लोगों ने इस जनादेश के

माध्यम से यह संकेत दिया है कि वे सुशासन, लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और विकास के लिए नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ खड़े होने का मन बना चुके हैं. यह चुनाव भाजपा की बंगाल में मजबूत हो चुकी जमीन पर शंका करने वाली धारणाओं को धता बताने वाला भी सिद्ध हुआ है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एकबार कहा था, 'भाजपा का स्वर्णकाल तब आएगा जब बंगाल और केरल जैसे राज्यों में भी भाजपा की सरकार होगी.' आज बंगाल उस कथन को सिद्ध करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है.



बैरकपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सभा में उमड़ा जनसैलाब

चयनित संदर्भ सूची

- 1. https://www.youtube.com/watch?v=LhYqfjEAdFg
- https://www.ichowk.in/politics/mamata-banerjee-political-standon-cbi-thrashed-by-supreme-court-ordering-kolkata-policecommissioner-rajeev-kumar-to-present-before-cbi/story/1/13887.html
- 3. https://www.patrika.com/state-news/bomb-blast-in-kolkata-local-train-many-injured-989468/
- 4. https://hindi.indiatvnews.com/india/politics-west-bengal-mamata-banerjee-s-cut-money-rate-card-tmc-leaders-face-cut-money-blowback-646295
- 5. https://pmuy.gov.in/
- 6. https://rightlog.in/2019/06/kolkata-decline-left-government-01/
- 7. https://hindi.opindia.com/politics/hindus-in-raiganj-west-bengal-stopped-from-voting-in-muslim-dominated-villages-report/
- 8. https://www.bbc.com/hindi/india-43962201
- http://www.nationalistonline.com/2019/06/20/bengal-suffers-from-dictatorship-rule-of-mamta/
- 10. https://www.patrika.com/kolkata-news/7-tribals-die-in-bengal-in-15-days-due-to-malnutrition-3705360/
- https://zeenews.india.com/hindi/india/west-bengal-doctorsuspended-after-he-post-on-facebook-about-dengue-and-bad-healtharrangement/350702
- 12. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/bengal-students-fare-poorly-in-higher-classes-ncert/articleshow/63473024.cms

- https://m.dailyhunt.in/news/india/hindi/hindusthan+samachar-epaper-hindusam/pulis+phayaring+me+do+chatro+ki+hatya+ke+khilaph+aan dolan+karegi+ebivipi-newsid-97470981
- 14. https://www.livehindustan.com/business/story-priyanka-lawyer-said-she-gets-bail-but-official-does-not-set-her-free-2531422.html
- 15. https://aajtak.intoday.in/story/west-bengal-panchayat-election-tmc-mamata-banerjee-winners-tpt-1-1000020.html
- 16. http://performindia.com/category/west-bengal-stories/
- https://www.btvi.in/news/have-you-met-shah-jahan--or-have-you-not-/137861
- https://aajtak.intoday.in/story/amit-shah-alleged-tmc-mamatabanerjee-ishwar-chandra-vidyasagar-statue-kolkata-road-showviolence-1-1083832.html
- 19. https://www.jagran.com/west-bengal/kolkata-lawyers-in-howrah-will-not-work-against-lathi-charge-for-april-29-till-lawyers-19169778.html
- https://zeenews.india.com/hindi/india/states/west-bengal-2-exstudents-dead-in-clash-erupt-in-dinajpur/449607
- 21. https://timesofindia.indiatimes.com/city/kolkata/west-bengal-rural-health-system-may-be-hit-hard-fears-government/articleshow/65364539.cms
- 22. https://www.jagran.com/west-bengal/kolkata-dengue-death-18626551.html
- 23. https://www.newsstate.com/india/news/calcutta-medical-college-row-students-threaten-mass-hunger-strike-principal-heckled-58257.html
- 24. https://twitter.com/BJP4India

- 25. https://twitter.com/BJP4Bengal?lang=en
- 26. https://www.jagran.com/elections/lok-sabha-democracy-ensanguined-in-west-bengal-713-companies-and-71-thousand-soldiers-deployed-yet-violence-continue-jagran-special-19223854.html
- https://www.financialexpress.com/india-news/west-bengal-election-2019-raiganj-violence-political-violence-west-bengal-has-bloodsoaked-history-of-electoral-violence/1552434/
- 28. https://mantraya.org/analysis-cattle-smuggling-from-india-to-bangladesh-scale-nexus-prevention-attempts/
- 29. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=176391
- https://www.ichowk.in/politics/mamata-banerjee-political-standon-cbi-thrashed-by-supreme-court-ordering-kolkata-policecommissioner-rajeev-kumar-to-present-before-cbi/story/1/13887.html
- https://aajtak.intoday.in/story/mamata-banerjee-not-to-come-in-prime-minister-narendra-modi-niti-aayog-meeting-1-1090900.html
- 32. https://www.newsstate.com/entertainment/bollywood/bhobishyoter-bhoot-illeffects-on-mamta-banerjee-supreme-court-hard-on-film-ban-82973.html
- https://aajtak.intoday.in/story/supreme-court-mamata-banerjee-government-contempt-notice-priyanka-sharma-release-1-1097535.
 html
- 34. http://www.bbnl.nic.in/actgps.aspx?langid=1&ls_id=9&l_id=9
- 35. https://hindi.rightlog.in/2019/02/mamata-madrasas-02/
- 36. https://hindi.mynation.com/news/mamata-budget-more-money-to-madrassa-than-higher-education-in-bengal-pmtagu

- 37. https://rightlog.in/2019/06/kolkata-decline-left-government-01/
- 38. https://nsp.gov.in/dashboard/
- 39. https://soilhealth.dac.gov.in/
- 40. https://sbm.gov.in/sbmReport/State.aspx
- 41. http://www.pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1576232
- 42. http://janaushadhi.gov.in/StoreDetails.aspx
- 43. http://sagarmala.gov.in/sites/default/files/List_of_Projects_in_West_ Bengal.pdf
- 44. http://www.ujala.gov.in/
- 45. https://community.data.gov.in/project-wise-amount-sanctioned-and-amount-spent-under-national-mission-for-clean-ganga-as-on-30-06-2017/
- 46. https://nsp.gov.in/dashboard/
- 47. https://soilhealth.dac.gov.in/
- $48.\ https://soilhealth.dac.gov.in/publicreports/dashboardtargetreport$
- 49. http://www.pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1576232
- 50. http://janaushadhi.gov.in/StoreDetails.aspx
- http://sagarmala.gov.in/sites/default/files/List_of_Projects_in_West_ Bengal.pdf
- 52. http://www.ujala.gov.in/
- 53. https://indianexpress.com/article/india/mamata-banerjee-bengal-women-maneka-gandhi-5552840/
- 54. https://digilocker.gov.in/public/dashboard#!
- 55. http://www.bbnl.nic.in/actgps.aspx?langid=1&ls_id=9&l_id=9
- 56. https://community.data.gov.in/project-wise-amount-sanctioned-

and-amount-spent-under-national-mission-for-clean-ganga-as-on-30-06-2017/

- 57. https://www.pmgdisha.in/
- 58. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=184325
- 59. https://pmuy.gov.in/released-connections.html
- 60. https://www.nfsm.gov.in/District/DistrictName2016.pdf
- 61. http://pib.nic.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1555855
- 62. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=186265
- 63. https://pmksy.gov.in/mis/rptAchievement.aspx
- 64. http://pmkvyofficial.org/Dashboard.aspx
- 65. 1231 km proposed to be constructed under Bharatmala
- 66. Pariyojana Phase-I
- 67. http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=184325







